@saahassamachar @saahassamachar @saahassamachar

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

राष्ट्रीय संस्करण

साहस समाचार

निष्पक्ष, निर्भीक, बेबाक

शिल्पा शिंदे के ऑर्डर पर फूट-फूटकर रोईं शिवांगी ...पेज-8

नई दिल्ली, मंगलवार, 14 जुलाई 2026, वर्ष-1, अंक-233, पृष्ठ-8, मूल्य-2 रुपए RNI No-DLHIN/25/A2841 www.saahassamachar.in

न्यायालय ने जांच के अनुरोध वाली याचिकाओं पर एसआईटी से स्थिति रिपोर्ट मांगी

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच रिपोर्ट मांगी

नई दिल्ली, एजेंसी।

उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का सोमवार को निर्देश दिया। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में निष्पक्ष और समयबद्ध जांच के अनुरोध वाली याचिकाओं पर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किया। तीन याचिकाकर्ताओं में से एक नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने का अनुरोध करते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया। उन्होंने राम मंदिर का प्रबंधन करने वाले श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) से ऑडिट कराने का भी अनुरोध किया। अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव ने भी इसी प्रकार के अनुरोधों वाली दूसरी याचिका दायर की है।

वहीं, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद सुधाकर सिंह द्वारा दायर तीसरी याचिका में उच्चतम न्यायालय की निगरानी में सीबीआई जांच के साथ-साथ ट्रस्ट के पूरे वित्तीय लेन-देन का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का अनुरोध किया गया है। इससे पहले न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने एक याचिकाकर्ता को मामले को शीघ्र सुनवाई के लिए बाद में उल्लेख करने की अनुमति दी थी।

अधिवक्ता अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि मंदिर ट्रस्ट के कामकाज, प्रशासन और कथित वित्तीय अनियमितताओं सहित अन्य कथित अवैधताओं की जांच के लिए सीबीआई के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जाना चाहिए।

याचिका में राय ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और ट्रस्ट को ऐसे नियामक, पर्यवेक्षी और ऑडिट तंत्र स्थापित एवं लागू करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है, जो जनहित की रक्षा कर सकें और करोड़ों श्रद्धालुओं तथा दानदाताओं का विश्वास बनाए रखें। याचिका में कहा गया है कि ट्रस्ट से जुड़े धन के गायब होने और अन्य कथित अनियमितताओं की खबरें अंततः सही साबित हों या नहीं, लेकिन इन रिपोर्टों ने अयोध्या की गरिमा की पुनर्स्थापना के लिए पीढ़ियों तक संघर्ष करने वाले लोगों में गहरी चिंता पैदा की है। याचिका में यह भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने इस मामले में प्राथमिकी या किसी नियमित आपराधिक मुकदमे के दर्ज किए बिना ही जांच शुरू कर दी।

याचिका के अनुसार, यह मामला केवल संज्ञेय अपराधों की संभावित जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे असंख्य श्रद्धालुओं और आम जनता की आस्था, भावनाएं तथा विश्वास भी सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। उल्लेखनीय है कि 13 जून को उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन के आरोपों के बाद मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी का गठन किया था।

इस एसआईटी में लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) किरण एस तथा विशेष सचिव (वित्त) नील रतन को शामिल किया गया है।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला : आठ आरोपियों की न्यायिक हिरासत 27 जुलाई तक बढ़ी

अयोध्या, एजेंसी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फैजाबाद की विशेष भ्रष्टाचार निवारण अदालत ने आठ आरोपियों की न्यायिक हिरासत सोमवार को 14 दिनों के लिए और बढ़ा दी। आरोपियों की पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि सोमवार को समाप्त हो रही थी।

अभियोजन के अनुसार, आरोपियों को अपर जिला न्यायाधीश प्रतिभा नारायण की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया, जहां से उन्हें 27 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष ने शुक्रवार को दो आरोपियों रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की पुलिस हिरासत की मांग की थी। अदालत इस मामले पर मंगलवार (14 जुलाई) को फैसला सुनाएगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, जांच के दौरान दोनों आरोपियों के बयानों से नयी जानकारियां मिली हैं, जिससे तथ्यों की पुष्टि करने और मंदिर के चढ़ावे के कथित गबन से जुड़े सबूत बरामद करने के लिए उनकी पुलिस हिरासत जरूरी हो गई है।

होर्मुज पार करने वाले जहाजों से लेंगे 20 प्रतिशत शुल्क: ट्रंप

दुबई ,एजेंसी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने अमेरिका को 'होर्मुज स्ट्रेट का संरक्षक' बताया। साथ ही यहां से गुजरने वाले जहाजों पर 20 प्रतिशत शुल्कु वसूलने की बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक तरह से 'होर्मुज स्ट्रेट' पर अमेरिका के नियंत्रण का दावा किया है। उनके अनुसार, यह समुद्री मार्ग अमेरिका की निगरानी में सभी देशों के लिए पूरी तरह से खुला रहेगा, केवल ईरान से जुड़े जहाजों और ग्राहकों पर इस मार्ग के इस्तेमाल पर रोक रहेगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्ले टफॉर्म 'ट्रुथ' पोस्टे में लिखा, होर्मुज स्ट्रेयट खुला है और यह ईरान के बिना भी खुला रहेगा। हम अब 'ईरानी नाकाबंदी' को फिर से लागू कर रहे हैं। इसका

मतलब सिर्फ इतना है कि ईरान के जहाजों या ईरान से जुड़े ग्राहकों के आने-जाने पर रोक होगी। बाकी सभी देशों के लिए इस समुद्री मार्ग का इस्तेमाल निष्पक्ष और खुला रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रंपति पोस्टर में लिखा, अब से अमेरिका को 'होर्मुज स्ट्रेलट का संरक्षक' कहा जाएगा। लेकिन निष्पक्षता के तौर पर इस जिम्मेदारी को निभाने में होने वाले सभी खर्चों के लिए अमेरिका को हर भेजे जाने वाले माल (कार्गो) पर 20 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जाएगा।

ताकि इस बेहद संवेदनशील और अस्थिर क्षेत्र की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने का काम किया जा सके। इस प्रक्रिया और इसकी व्यवस्था को तुरंत शुरू किया जाएगा। अमेरिका और ईरान दोनों ही होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अपना-अपना दावा कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिका इस मार्ग को पूरी तरह सुरक्षित और अपने नियंत्रण में बता रहा है तो दूसरी तरफ ईरान लगातार जहाजों को यहां से न गुजरने की चेतावनी दे रहा है। ईरान की ओर से फिलहाल के लिए इस मार्ग के बंद होने के दावा किया जा रहा है।

एक दिन पहले ही आईआरजीसी की नौसेना ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेहट में विदेशी ताकतों के गैरकानूनी हस्तक्षेप की वजह से पैदा हुई असुरक्षा के चलते यह जलमार्ग अगली सूचना तक बंद रहेगा।

भाजपा ने उमर अब्दुल्ला को 100 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा

जम्मू,एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जम्मू-कश्मीर इकाई ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को एक कानूनी नोटिस भेजा है। इसमें उनसे उन कथित बयानों को वापस लेने की मांग की गई है, जिनमें उन्होंने पार्टी पर पैसे और मंत्री पद का लालच देकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। नोटिस में सात दिनों के भीतर बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगने को कहा गया है और ऐसा न करने पर 100 करोड़ रुपये के मानहानि के मुकदमे सहित दीवानी और आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है।

कानूनी नोटिस के अनुसार राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सत पाल शर्मा के निर्देश पर वकील परिमोक्ष सेठ ने अब्दुल्ला को यह नोटिस जारी किया है।

भ्रष्टाचार, वसूली तंत्र में बदल चुकी शिक्षा व्यवस्था: राहुल गांधी

नई दिल्ली, एजेंसी।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि देश की शिक्षा व्यवस्था भ्रष्टाचार, वसूली और पक्षपाती होकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इसलिए छात्रों को अब संगठित होकर लड़ना होगा ताकि 'छात्रों की गूंज' अभियान शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के लिए क्रांति का माध्यम बने।

गांधी ने सोमवार को सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक संदेश में कहा कि 'भ्रष्ट, अन्यायी, पक्षपाती और बेईमान' जैसे शब्द उनके नहीं, बल्कि देश के छात्रों के हैं, जो आज की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चों का भविष्य संवारने के लिए बनाई गई शिक्षा व्यवस्था अब एक 'बेईमान

वसूली तंत्र' में बदल चुकी है, जो छात्रों और उनके परिवारों को कर्ज, तनाव और निराशा की ओर धकेल रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार ने पेपर लीक माफिया को जन्म दिया है, जो लाखों छात्रों की वर्षों की मेहनत एक झटके में बर्बाद कर देता है। उनका आरोप था कि इस व्यवस्था में दोषी वेंडरों और अधिकारियों को कार्रवाई के बजाय नए टेंडर और तरक्की मिलती है जबकि सजा छात्र पाते हैं और उन्हें टूटे सपनों और अनिश्चित भविष्य के साथ छोड़ दिया जाता है।

सार समाचार

आर. वैरमुत्तु को मिला 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार

नई दिल्ली,एजेंसी। भारतीय साहित्य के प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 सोमवार को तमिल के प्रख्यात कवि, साहित्यकार और गीतकार आर. वैरमुत्तु को प्रदान किया गया। राष्ट्रीय राजधानी स्थित चिन्मय मिशन ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में भारत के वरिष्ठ राजनेता, प्रसिद्ध चिंतक और विद्वान डॉ. कर्ण सिंह ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। पुरस्कार के तहत श्री वैरमुत्तु को 11 लाख रुपये की नकद राशि, वाग्देवी (मां सरस्वती) की कांस्य प्रतिमा तथा प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया। समारोह में भारतीय ज्ञानपीठ के ट्रस्टी मुदित जैन, प्रबंध न्यासी साहू अखिलेश जैन, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रवर परिषद की अध्यक्ष डॉ. प्रतिभा राय, महाप्रबंधक आर.एन. तिवारी सहित देशभर के साहित्यकार, लेखक, शिक्षाविद और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

एनटीए ने जारी की ओएमआर शीट और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स

नई दिल्ली,एजेंसी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने नीट(यूजी)-2026 की पुनर्परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के लिए ओएमआर उत्तर पत्रक की स्कैन कॉपी और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स जारी कर दिये हैं। एनटीए ने सोमवार को सार्वजनिक सूचना जारी कर बताया कि अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर अपनी ओएमआर शीट और रिकॉर्डेड उत्तर देख सकते हैं तथा यदि किसी उत्तर पर आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन चुनौती दर्ज करा सकते हैं। एजेंसी ने कहा कि रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स पर आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया 13 जुलाई से शुरू हो गयी है और 15 जुलाई को सुबह 11 बजे तक जारी रहेगी।

भारत और जापान ने हिन्द प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्धता दोहराई

नई दिल्ली,एजेंसी। भारत और जापान ने स्वतंत्र, खुले और नियमों पर आधारित हिन्द प्रशांत क्षेत्र की पुरजोर वकालत करते हुए इसे बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि दोनों देशों के बीच आज जापान की राजधानी टोक्यो में 8वीं रक्षा नीति वार्ता हुई। वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने और जापानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए रक्षा उप-मंत्री कानो कोजी ने किया। दोनों पक्षों ने पिछली रक्षा नीति वार्ता के बाद से द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की।

आईबी अफसर हत्या मामले में ताहिर हुसैन दोषी करार

नई दिल्ली, एजेंसी।

दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो (आईबी) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में यहाँ की एक अदालत ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को सोमवार को दोषी करार दिया।

अदालत ने हुसैन को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188, 153ए, 147, 148, 149, 365 और 302 के तहत अपराधों के लिए दोषी करार दिया। अदालत ने सजा पर बहस के लिए तारीख तय नहीं की है। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने अदालत के फ़ैसले का स्वागत किया है। उन्होंने सवाददाताओं से बातचीत में कहा कि आम आदमी पार्टी के कई राष्ट्रविरोधी तत्वों से गहरे संबंध रहे हैं, जो समय-समय पर उजागर होते रहे हैं। वर्ष 2020 के दंगों में ताहिर हुसैन इसका एक प्रमुख उदाहरण है।उन्होंने

कहा कि वर्ष 2020 के दंगों का एक अन्य आरोपी खालिद सैफी भी इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के दौरान पूर्व अरविंद केजरीवाल की टीम के साथ कार्य कर चुका है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 तक, जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई, तब तक अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली दंगों के एक अन्य आरोपी उमर खालिद के मामलों में भी अत्यधिक नरम रुख अपनाया।

न्यूनतम सुशासन, अधिकतम लीपापोती है मोदी सरकार की नीति: कांग्रेस

नई दिल्ली, एजेंसी।

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचार के मामलों को दबाने तथा जवाबदेही से बचने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी सरकार की असली नीति 'न्यूनतम सुशासन, अधिकतम लीपापोती' की रही है।कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने सोमवार को सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक बयान में कहा कि मई 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने 'ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा' का नारा दिया था। लेकिन यह दावा पूरी तरह से खोखला साबित हुआ है।

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने आठ नवंबर 2016 की मोदी की नोटबंदी की घोषणा को 'संगठित लूट और वैध लूट' बताने का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके बाद गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (जीएसपीसी) को ओएनजीसी में मिलाकर 20 हजार करोड़ रुपये के

कथित घोटाले को छिपाने।

चुनावी बॉण्ड योजना के माध्यम से कथित 'चंदा दो, धंधा लो' व्यवस्था, राफेल सौदे पर उठे सवाल, बिना पारदर्शिता और जवाबदेही वाले पीएम केयर्स फंड तथा आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी प्रमुख सरकारी योजनाओं में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्टों में सामने आई अनियमितताओं का उल्लेख किया। रमेश ने कहा कि पिछले कुछ सप्ताह में कई और घटनाएं सामने आई हैं, जिन्होंने 'ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा' के दावे की वास्तविकता उजागर कर दी है।

उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला देश की आस्था के साथ धोखा बताया और कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के आदेश के बावजूद अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर अपने परिजनों को कथित रूप से लाभ पहुंचाने के गंभीर आरोप लगे हैं और वह भी पद पर बने हुए हैं।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों को विभिन्न प्रकार के आर्थिक प्रलोभन देकर तोड़ा जा रहा है। केंद्र सरकार में एक राज्य मंत्री अपने ही मंत्रालय की योजना का लाभ लेने के आरोपों के बावजूद पद पर बने हुए हैं। इसी तर्ज पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री के चार करीबी सहयोगियों को अचानक हटाए जाने, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ई-20 नीति से केंद्रीय मंत्री के परिवार को कथित लाभ पहुंचाने तथा दिल्ली की मुख्यमंत्री के परिवार के प्रशासनिक कार्यों में कथित हस्तक्षेप जैसे मामलों का भी उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि श्री मोदी ऐसे शिक्षा मंत्री को भी पद पर बनाए हुए हैं जिनके कार्यकाल में परीक्षा व्यवस्था भ्रष्ट और समझौतापूर्ण हो गई है तथा इससे देश के करोड़ों युवाओं की उम्मीदों और भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है।मोदी सरकार की पहचान अब 'न्यूनतम सुशासन, अधिकतम लीपापोती' बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का वास्तविक मंत्र 'ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा' नहीं, बल्कि 'खाऊँगा, खाने दूँगा और खिलाऊँगा' बन गया है और अधिकतम सुशासन की बात करने वाली सरकार का काम 'न्यूनतम सुशासन, अधिकतम लीपापोती' की नीति पर आधारित हो गया है।

जून में खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 5.32 प्रतिशत हो गयी, जबकि मई में यह 4.78 प्रतिशत थी

महंगाई का झटका: जून में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.38 प्रतिशत हुई

नई दिल्ली,एजेंसी।

पश्चिम एशिया संकट और मानसून की चिंताओं के बीच देश में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित महंगाई दर जून 2026 में बढ़कर 4.38 प्रतिशत हो गयी। विश्लेषकों के अनुसार, नयी सीरीज होने के बाद 16 महीने में मुद्रास्फीति का यह उच्चतम स्तर है। इससे रिजर्व बैंक पर नीतिगत ब्याज दर बढ़ाने का दबाव बन सकता है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि मई में खुदरा मुद्रास्फीति 3.93 प्रतिशत (संशोधित आंकड़ा) थी। जून माह में बढ़ोतरी मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं, परिवहन सेवाओं और ईंधन की कीमतों में वृद्धि के कारण हुई।

जून में खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 5.32 प्रतिशत हो गयी, जबकि मई में यह 4.78 प्रतिशत थी। ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई का दबाव शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक बना रहा। जून में ग्रामीण खुदरा महंगाई 4.74 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 3.92 प्रतिशत रही। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य महंगाई 5.45 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 5.09 प्रतिशत रही। जून में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 107.00 रहा जो एक माह पूर्व 105.91 था। जून 2026 में चांदी के आभूषणों के खुदरा मूल्य 133.21 प्रतिशत ऊंचे रहे लेकिन मई (155.25 प्रतिशत) की तुलना में इसमें नरमी रही है। माह के दौरान अदरक का खुदरा भाव (54.41 प्रतिशत) , सोना, हीरा और प्लैटिनम के आभूषणों का भाव (36.82 प्रतिशत), टमाटर का 31.92 प्रतिशत और किशमिश तथा मुनक्का का 20.52 प्रतिशत ऊंचा था। इसके विपरीत आलोच्य माह में आलू के खुदरा भाव पिछले साल से 20.34 प्रतिशत नीचे रहे जबकि मटर 9.67 प्रतिशत नीचे आ गयी।

मोटर कार और जीप, जीरा, तथा मोटरसाइकिल और स्कूटर की कीमतें भी पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में कम रहीं।

पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष राजीव जुनेजा ने कहा, ₹हालांकि, समग्र खुदरा महंगाई अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर बनी हुई है, लेकिन खाद्य महंगाई पर लगातार बना दबाव नीति-निर्माताओं के लिए चिंता का विषय है, और इस पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है।

पीएचडी चैंबर के महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. रंजीत मेहता ने कहा, ग्रामीण और शहरी महंगाई के बीच बढ़ता अंतर इस बात की ओर संकेत करता है कि आपूर्ति व्यवस्था (सप्लाई साइड) को अधिक कुशल बनाने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास लगातार जारी रखने की आवश्यकता है। आने वाले समय में अनुकूल मानसून और प्रभावी वितरण प्रणाली खाद्य महंगाई के दबाव को कम करने के साथ-साथ उपभोग और निवेश को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

पश्चिम बंगाल में ट्रॉलर डूबी, नौ मछुआरों के शव बरामद

कोलकाता, एजेंसी।

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में बक्खाली तट के पास एक हफ्ते से ज्यादा समय से लापता एक ट्रॉलर के डूबने से नौ मछुआरों की मौत हो गयी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुखद हादसे पर गहन दुख व्यक्त किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से प्रत्येक मृतक के परिजन को दो लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं, समुद्र में लापता छह अन्य मछुआरों की तलाश के लिए युद्ध स्तर पर बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के मुताबिक कि बंगाल की खाड़ी में खराब मौसम के दौरान ट्रॉलर पलट गया था, जिससे मछुआरे समुद्र में गिर गये। दुर्घटना के सटीक कारणों का पता विस्तृत जांच के बाद ही चल पायेगा।

'मां काली' नाम का यह ट्रॉलर दो जुलाई को पूर्वी मिदनापुर के दीघा स्थित शंखपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ मछली पकड़ने के नियमित अभियान पर निकला था। अधिकारियों के अनुसार, पांच जुलाई के बाद नाव से संपर्क टूट गया। इसके बाद तटरक्षक बल, पुलिस, वन विभाग और स्थानीय मछुआरों को मिलाकर एक बड़ा खोज अभियान शुरू किया गया। आठ दिनों की लगातार तलाश के बाद डूबे हुए ट्रॉलर को बक्खाली तट से लगभग 35 किलोमीटर दूर 'बाघेर चर' के पास खोज निकाला गया।

रविवार दोपहर गोबर्धनपुर पुलिस थाना कर्मियों, वन विभाग और भारतीय तटरक्षक बल ने डूबे पोत की पहचान की।

ट्रैफिक नियम तोड़े...एक सप्ताह में 14,527 चालान कटे

गुरुग्राम,एजेंसी।

यातायात पुलिस ने चालान नहीं सलाम अभियान के तहत पिछले एक सप्ताह के दौरान सड़कों पर यातायात नियम तोड़ने वाले 14,527 वाहनों के चालान काटे हैं। यातायात पुलिस ने मैन्युअली तौर पर वाहनों के चालान काटने के दौरान चालकों पर 1,31,97,600 रुपये का जुर्माना लगाया है। पुलिस ने दिल्ली-जयपुर हाईवे व द्वारका एक्सप्रेसवे पर सख्ती बढ़ाई है, ताकि यातायात नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाए।

पुलिस ने 6 जुलाई से 12 जुलाई तक कुल 14,527 वाहनों के चालान काटे। इनमें मैन्युअली तौर पर 8,574 वाहनों के चालान शामिल हैं। इनमें गलत दिशा में वाहन चलाने पर 915, रोड मार्किंग 117, दोपहिया वाहन पर पिलियन राइडर बिना हेलमेट 625, बिना सीट बेल्ट 278, दोपहिया चालक बिना हेलमेट 767, शराब पीकर वाहन चलाने पर 76, नो पार्किंग 558, खतरनाक यू-टर्न 93, दोपहिया वाहन पर ट्रिपल राइडिंग 124, ओवरस्पीड 47, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग 14, ध्वनि प्रदूषण 14 और लेन चेंज 1234 चालान शामिल हैं।

वहीं, हाईवे, एक्सप्रेसवे व अन्य सड़कों पर लगे कैमरों के माध्यम से 5,953 वाहनों के चालान काटे गए। इनमें लेन चेंज 1858, नो एंट्री 2706, ओवरस्पीडिंग 418, दोपहिया वाहन पर पिलियन राइडर बिना हेलमेट 83, दोपहिया चालक बिना हेलमेट 169, दोपहिया वाहन पर ट्रिपल राइडिंग 23, बिना सीट बेल्ट 303, प्रदूषण 351 और फ्रंट पैसेंजर बिना सीट बेल्ट 42 चालान शामिल है।

यातायात पुलिस ने एक जुलाई से 12 जुलाई तक शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई करते हुए 275 चालकों को पकड़ा। यातायात पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर नाका लगाकर जांच के दौरान 275 चालकों को शराब पीकर गाड़ी चलाने पर चालान काटे व उनके ड्राइविंग लाइसेंस को तीन माह के लिए सस्पेंड किया है। इस दौरान पुलिस ने एक वाहन को भी जब्त किया है।

सड़कों पर यातायात नियमों को तोड़ने वाले चालकों पर कार्रवाई करते हुए चालान काटे जा रहे हैं। शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के लिए सस्पेंड किए जाते हैं। इस अवधि के दौरान उक्त चालक किसी भी वाहन को चला नहीं सकता। अगर बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

बीजेपी संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर राजनीतिक दलों को तोड़ रही: दीपेन्द्र हुड्डा

गुरुग्राम,एजेंसी।

सांसद दीपेन्द्र सिंह हुड्डा ने रविवार को संत कबीर शिरोमणि सम्मान समारोह में भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर राजनीतिक दलों को तोड़ने का काम कर रही है। साथ ही कहा कि कांग्रेस सरकार के समय मिलेनियम सिटी के रूप में पहचान बनाने वाले गुरुग्राम को भाजपा ने एक बारिश में डूबने वाले शहर की पहचान दे दी है। समारोह में संत कबीर को दीपेन्द्र हुड्डा ने नमन किया।

उन्होंने ने आरोप लगाया कि भाजपा लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। भाजपा ने विभिन्न राज्यों में राजनीतिक दलों को तोड़ने का काम किया है। हरियाणा में भी पिछले 12 वर्षों से हर वर्ग की उपेक्षा की गई है। उन्होंने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा ने चुनाव आयोग और धनबल का दुरुपयोग कर सत्ता हासिल की। दीपेन्द्र ने कहा कि भाजपा ने चुनाव से पहले किए गए वादे पूरे नहीं किए।

गुरुग्राम के विकास पर बोलते हुए दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में शहर को मिलेनियम सिटी के रूप में विकसित किया गया। आज एक बारिश में पूरा शहर जलभराव से जूझता है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 12 वर्षों में गुरुग्राम में एक नया सरकारी अस्पताल तक नहीं बन पाया। कांग्रेस सरकार के दौरान 86 किलोमीटर मेट्रो का निर्माण हुआ, जबकि उसके बाद शहर में मेट्रो विस्तार एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा। समारोह में सांसद कर्मवीर बौद्ध, विधायक शकुंतला खटक, हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज, गुरुग्राम ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष वर्धन यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे।

बारिश के पानी में उतरकर व्यायाम कर रहे लोग

ट्रांस हिंडन,एजेंसी।

ट्रांस हिंडन क्षेत्र के कई पार्कों की बदहाल स्थिति के कारण लोगों की सुबह-शाम की सैर प्रभावित हो रही है। वैशाली और डीएलएफ कॉलोनी समेत कई इलाकों के पार्कों में जगह-जगह गंदगी फैली हुई है और तीन दिन पहले हुई बारिश का पानी अभी तक जमा है। इससे लोगों को पार्कों में सैर और व्यायाम करने में दिक्कत हो रही है। लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। मजबूरी में पानी में उतरकर व्यायाम करना पड़ रहा है। डीएलएफ कॉलोनी स्थित एकता पार्क सहित आसपास के कई पार्कों में बारिश का पानी अभी तक भरा हुआ है। जलभराव होने से लोगों का पार्कों में टहलना और व्यायाम करना मुश्किल हो गया है। स्थानीय निवासी

मनोज कुमार ने बताया कि पार्क में घुटनों तक पानी जमा है।

इसके अलावा वैशाली के भी कई पार्कों के हाल खस्ताहाल है। स्थानीय निवासी सुनील वैध ने बताया कि इलाके के चार पार्कों की स्थिति अधिक गंभीर है। पोडियम पार्क, कृष्णा वाटिका और अंबेडकर पार्क में बारिश के बाद से चारों और गंदगी फैली हुई है। कचरा गीला होने के कारण इससे दुर्गंध भी आ रही है। इसके अलावा पिंक पार्क भी जर्जर होता जा रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया है कि देखरेख के अभाव में पार्कों की यह स्थिति होती जा रही है। जिससे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं समेत अन्य लोगों की सुबह की सैर प्रभावित हो रही है। लोगों ने नगर निगम से मांग कि है की पार्कों की स्थिति में सुधार किया जाए।उद्यान विभाग सहायक अभियंता का कहना है कि मामला संज्ञान में नहीं है। मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।

अलग-अलग सड़क हादसों में महिला सहित चार घायल

गुरुग्राम,एजेंसी।

जिले में हुए तीन अलग-अलग सड़क हादसों में एक महिला सहित चार लोग घायल हो गए। घायलों व उनके परिजनों की शिकायतों के आधार पर पुलिस ने 12 जुलाई को बादशाहपुर थाने, बिलासपुर थाने व सेक्टर-10 थाने में अज्ञात वाहन चालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। संबंधित थानों की पुलिस तीन मामलों में आगामी कार्रवाई कर रही है। श्याम कुंज के गली-4 निवासी अश्वनी कुमार ने बादशाहपुर थाने में दी शिकायत में बताया कि वह दोस्त प्रवीन सैनी के साथ 9 जुलाई की रात को झाड़सा गांव से घर जा रहा था।

पिरामिड सोसाइटी के सामने फ्लाईओवर रोड पर पहुंचे तो अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इससे वे दोनों घायल हो गए और राहगीरों ने उनको पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर अश्वनी कुमार व प्रवीन सैनी को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों अस्पताल में उपचाराधीन हैं। दूसरे मामले में बहोड़ा कलां गांव निवासी पुस्कर भारद्वाज ने बिलासपुर थाने में दी शिकायत में बताया कि वे 9 जुलाई की रात बाइक से बिलासपुर से गांव आ रहे थे। रात करीब 9.15 बजे जीएलएस कंपनी के पास कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उनको काफी चोटें आई व उनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

वहीं, तीसरे मामले में वजीरपुर गांव निवासी बिजेंद्र ने सेक्टर-93 पुलिस चौकी में दी शिकायत में बताया कि वे 6 जुलाई की शाम करीब 4.30 बजे पत्नी के साथ पैदल ही मेवका की ओर जा रहे थे। उनकी पत्नी थोड़ी आगे चल रही थीं। इसी दौरान सामने से आ रही बाइक ने पत्नी गीता को टक्कर मार दी। हादसे में चोट लगने से उनकी पत्नी घायल हो गई। राहगीरों की मदद से उन्होंने पत्नी को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे के बाद बाइक सवार दोनों युवक वाहन सहित मौके से भाग गए। तीनों मामलों में संबंधित थानों की पुलिस वाहनों की पहचान कर जल्द ही चालकों को जांच में शामिल करेगी। वाहनों के नंबरों के आधार पर उनकी पहचान की जा रही है।

सोसाइटी में सिर्फ एक ही लिफ्ट चलने से परेशानी

ग्रेटर नोएडा,एजेंसी।

विक्ट्री वन सेंट्रल सोसाइटी के लोग बिल्डर द्वारा कार्य को पूरा न करने के कारण परेशान है। लोगों का आरोप है कि सभी टावरों में केवल एक लिफ्ट ही संचालित की गई है, जिसके कारण आने-जाने में सभी को परेशानी होती है। वहीं, इसी सुविधा की मांग को लेकर अब लोगों ने दोबारा से प्राधिकरण से मांग की है। साथ ही, सोसाइटी में क्लबहाउस, पार्किंग एरिया, एसटीपी सहित अन्य काम अधूरे पड़े हुए हैं। विक्ट्री वन सेंट्रल सोसाइटी के निवासियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

सोसाइटी में रहने वाले प्रशांत ने बताया कि सोसाइटी में करीब 450 परिवार रहते हैं। जिन्हें मूलभूत सुविधाएं तक ठीक से नहीं मिल रही हैं।

तीन भाईयों ने युवक के साथ मारपीट की

लोनी,एजेंसी।

लोनी थाना क्षेत्र में रोड पर खड़े युवक के साथ तीन भाईयों ने मारपीट की। आरोप है कि तीनों पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। लोनी थाना क्षेत्र की इकराम नगर कॉलोनी में आरिफ रहते है। उन्होंने बताया कि शनिवार रात करीब आठ बजे वह साथी के साथ रूप नगर कॉलोनी में बैंक के सामने खड़े थे। इस दौरान रूपनगर कॉलोनी में रहने वाला फईम किसी बुजुर्ग से अभद्रता कर रहा था। उनके द्वारा विरोध करने पर फईम ने अपने दो भाईयों को नवीन और नफीस को मौके पर बुला लिया। आरोप है कि तीनों भाईयों ने उनके साथ मारपीट की। शोर मचाने पर लोगों को एकत्र होता देख तीनों बाइक पर बैठकर मौके से फरार हो गए। उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस से की।

तीन तक चले विशेष अभियान में 417 आरोपी गिरफ्तार

फरीदाबाद,एजेंसी।

आपराधिक गतिविधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने 10 से 12 जुलाई तक जिलेभर में तीन दिवसीय विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान पुलिस ने विभिन्न मामलों में 417 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं 47 गुमशुदा व्यक्तियों को तलाश कर उनके परिजनों से मिलाया गया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि अभियान के दौरान नशा तस्करों के खिलाफ सबसे अधिक फोकस रखा गया। एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज नौ मामलों में पुलिस ने तीन किलोग्राम से अधिक गांजा, 25 प्रतिबंधित इंजेक्शन और 1.3 ग्राम एमडीएमए बरामद करते हुए नौ नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 17 देसी कट्टे बरामद कर 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शराब तस्करी पर कार्रवाई के दौरान आबकारी अधिनियम के तहत 79 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से देसी और अंग्रेजी शराब की दो हजार बोतल और चार लीटर कच्ची शराब बरामद की है।

जुआ खेलने और खिलाने वालों के खिलाफभी पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने 54 मामलों में 64 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक लाख 47 हजार 590 रुपये की नकदी बरामद किए। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग मचाने और शांति भंग करने वाले 57 लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की। पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि विशेष अभियान का उद्देश्य जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत करना, वांछित एवं जघन्य अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करना है।

नीमका जेल हत्याकांड में गैंगस्टर अरुण चौधरी पर हत्या का आरोप तय

फरीदाबाद,एजेंसी।

हरियाणा के फरीदाबाद की नीमका जिला जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड में बंद आतंकी आरोपित अब्दुल रहमान की हत्या के मामले में अदालत ने गैंगस्टर अरुण चौधरी के खिलाफ हत्या तथा साथी बंदी को धमकी देने के आरोप तय कर दिए हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने सोमवार को आरोप तय करने के बाद मामले में नियमित ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया।

अरुण चौधरी फिलहाल करनाल जेल में बंद है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई कार्यवाही के दौरान उसने स्वयं को निर्दोष बताते हुए मुकदमा चलाने की मांग की।घटना के बाद न्यायिक जांच के साथ-साथ जेल की सुरक्षा व्यवस्था की भी जांच कराई गई थी। अब अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद इस बहुचर्चित हत्याकांड का नियमित ट्रायल शुरू होगा। अभियोजन पक्ष अदालत में गवाहों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोप साबित करने का प्रयास करेगा, जबकि बचाव पक्ष ने आरोपों से इनकार किया है।

उल्लेखनीय है कि यह घटना आठ फरवरी की रात नीमका जिला जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड में हुई थी। जांच के अनुसार जम्मू-कश्मीर के आरएसपुरा निवासी अरुण चौधरी ने बैरक में बंद अब्दुल रहमान पर गमछे में पत्थर बांधकर हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। घटना के बाद जेल प्रशासन और पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। अब्दुल रहमान उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के मिल्कीपुर का रहने वाला था। उसे मार्च 2025 में गुजरात एटीएस और हरियाणा एसटीएफ ने फरीदाबाद के पाली क्षेत्र से गिरफ्तार किया था।

जांच एजेंसियों का आरोप था कि वह अयोध्या स्थित राम मंदिर पर हमले की साजिश रच रहा था। उसके कब्जे से दो हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए थे और उसके खिलाफ यूएपीए सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

आगरा नहर में मिला महिला का शव, नहीं हो पाई पहचान

फरीदाबाद,एजेंसी।

सोमवार को आगरा नहर से एक अज्ञात महिला का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। शव चंदावली पुल के पास नहर में बहता हुआ दिखाई देने पर स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को नहर से बाहर निकलवाया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। जांच अधिकारी लाल शर्मा ने बताया कि किसी राहगीर ने आगरा नहर में एक महिला का शव बहते हुए देखा था। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला।

शुरुआती जांच में महिला की पहचान नहीं हो सकी है, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई दस्तावेज या सामान नहीं मिला जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। पुलिस के अनुसार महिला के शरीर पर किसी प्रकार के चोट या संघर्ष के स्पष्ट निशान भी नहीं मिले हैं। मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। फिलहाल पुलिस आसपास के थाना क्षेत्रों में गुमशुदगी के मामलों की जानकारी जुटा रही है और महिला की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

हाथ बांधकर महिला के साथ नहर में कूदा युवक, दोनों के शव बरामद

फरीदाबाद,एजेंसी।

बीपीटीपी पुल के पास आगरा नहर में कूदने वाले महिला और युवक के शव एसडीआरएफ की टीम ने सोमवार को शाहपुर कलां गांव के पास नहर से बरामद कर लिया है। दोनों का एक हाथ आपस में बंधा हुआ है। इससे अनुमान है कि युवक ने पहले महिला को हथौड़ा मारकर घायल किया, इसके बाद डाटा केबल से उसका हाथ अपने हाथ में बांधकर नहर में छलांग लगा दी। पुलिस ने इस मामले में महिला के पति की शिकायत पर युवक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। वहीं दूसरी तरफ युवक के स्वजन ने इसे साजिश के तहत हत्या बताते हुए गहन कार्रवाई की मांग की है।

महिला की पहचान सेक्टर-31 की रहने वाली रश्मि उर्फ रजनी के रूप में हुई थी, वह मेकओवर आर्टिस्ट के तौर पर काम करती थी। वहीं युवक का नाम आकाश उर्फ अक्कू है जो एतमादपुर गांव में रहता था और द्रोणाचार्य जिम में वर्कआउट करता था और ड्राइवर का काम करता था। मृतका के पति शिवम ने शिकायत में बताया है कि रजनी भी उसी जिम में वर्कआउट करती थी। दोनों की पहचान वहीं पर हुई थी। पति का आरोप है कि जिम में अक्कू ने रजनी को परेशान करना शुरू कर दिया था। रजनी ने यह बात पति को बताई थी। इसके बाद पति ने अक्कू से बात की तो उसने माफी मांग ली थी।

पिछले करीब 10 दिन से वह उसे फिर से परेशान कर रहा था। शनिवार को वह उससे बात करने की कहकर घर से कार लेकर निकली थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला कार चला रही थी और युवक साथ वाली सीट पर बैठा था। आरोप है कि युवक ने कार के अंदर ही रजनी पर हथौड़े से कई वार किए। महिला जान बचाने के लिए कार से बाहर निकली, लेकिन आरोपित उसे पकडक़र नहर किनारे ले गया और उसके साथ आगरा नहर में छलांग लगा दी। स्कूटी सवार दो युवकों ने पूरी घटना देखी और पास मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को सूचना दी।

पुलिस ने कार से खून से सना हथौड़ा और महिला के बाल बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि युवक वारदात की तैयारी करके आया था। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया है। शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल भिजवा दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ युवक के बहनोई अजय नागर ने इसे हत्या बताया है। उसका कहना है कि साजिश के तहत आकाश को बुलाया गया। इसके बाद दोनों की हत्या की गई है।

समझौता लागू नहीं होने पर पालिका व फायर कर्मियों ने हड़ताल का ऐलान किया

फरीदाबाद,एजेंसी।

नगरपालिका कर्मचारी संघ और हरियाणा अग्निशमन कर्मचारी यूनियन की ओर से दौलतराम धर्मशाला में जिला स्तरीय रैली आयोजित की गई। रैली में कर्मचारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए 6, 7 और 8 अगस्त को प्रदेशव्यापी तीन दिवसीय हड़ताल करने की घोषणा की। रैली की अध्यक्षता जिला प्रधान दलित बोहत ने की, जबकि संचालन जिला सचिव अनिल चंडालिया ने किया। इसमें नगरपालिका कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री, महासचिव मांगेराम तिगरा, उप महासचिव सुनील चंडालिया तथा हरियाणा अग्निशमन कर्मचारी यूनियन के राज्य प्रधान राजेंद्र सिंह समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री ने कहा कि 13 मई की वार्ता में सरकार ने कर्मचारियों की 17 प्रमुख मांगों पर सहमति जताते हुए 30 जून तक आदेश जारी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई पत्र जारी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट है कि सरकार की नीयत में खोट है और कर्मचारियों के साथ वादाखिलाफी की गई है। उन्होंने बताया कि प्रमुख मांगों में कच्चे और अनुबंधित कर्मचारियों को नियमित करना, ठेका प्रथा समाप्त करना, न्यूनतम वेतन, ईएसआई-ईपीएफ की सुविधा, रिक्त पदों पर भर्ती, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति सम्मान राशि और फरीदाबाद अग्निकांड में शहीद फायर कर्मियों के परिजनों को आर्थिक सहायता और रोजगार देना शामिल है।

RNI.No DLHIN/25/A2841
स्वामी, प्रकाशक, संपादक देवेंद्र सिंह तोमर एवं मुद्रक रवि भारद्वाज मै. मारुती नंदन प्रिंटर्स एवं पब्लिशर, शक्ति कॉम्प्लेक्स 6/18, समयपुर इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली 110042 से मुद्रित एवं हॉउस नंबर 16/ 9980, गली नंबर-5, सराय रोहिल्ला न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-110005 से प्रकाशित।
संपादकीय कार्यालय - B4/265B केशव पुरम नई दिल्ली -110005। फोन-011-40106508
मोबाइल-9911466900/ 8076353913। Email.saahassamachardainik@gmail.com
संपादक देवेंद्र सिंह तोमर
इस अंक में प्रकाशित खबरों एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। किसी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा नई दिल्ली के न्यायालय में होगा।

रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया एआई-संचालित 'डस्ट पोर्टल 2.0' निर्माण स्थलों की होगी लाइव मॉनिटरिंग

जीआईएस मैपिंग, 360 डिग्री कैमरों और एआई सेंसर से लैस प्लेटफॉर्म देगा ऑटोमैटिक प्रदूषण अलर्ट।

नई दिल्ली,साहस समाचार।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को एआई-संचालित 'डस्ट पोर्टल 2.0'-डस्ट पॉल्यूशन कंट्रोल सेल्फ-असेसमेंट वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ किया। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की ओर से विकसित यह अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म एआई की सहायता से निर्माण एवं विध्वंस स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों की वास्तविक समय में निगरानी करेगा। इसके माध्यम से परियोजना संचालकों को स्व-मूल्यांकन की सुविधा मिलेगी और डेटा आधारित निगरानी और एनफोर्समेंट को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा।

इस अवसर पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा सहित संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान डस्ट पोर्टल 2.0 का लाइव प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें दिखाया गया कि किस प्रकार एआई निगरानी व्यवस्था को अधिक कुशल, सटीक और प्रभावी बना सकती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली मंश वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई केवल सख्त नियमों से नहीं, बल्कि आधुनिक और स्मार्ट प्रशासनिक प्रणालियों से भी लड़ी जाएगी। डस्ट पोर्टल 2.0 निर्माण स्थलों पर धूल प्रदूषण की निगरानी और प्रबंधन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा।

उन्होंने कहा कि एआई और डिजिटल तकनीक के माध्यम से हमारी सरकार अनुपालन प्रक्रिया को सरल, निगरानी को अधिक प्रभावी और एनफोर्समेंट को अधिक पारदर्शी बना रहे हैं। यह प्लेटफॉर्म सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक निर्माण एजेंसी स्वच्छ और प्रदूषण-मुक्त दिल्ली के निर्माण में सक्रिय भागीदार बने। भविष्य में चालान प्रक्रिया को भी पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है ताकि पोर्टल के माध्यम से सीधे नोटिस और चालान जारी किए जा सकें तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता या असुविधा की संभावना समाप्त हो सके।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए नवाचार और तकनीक आधारित समाधानों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का लक्ष्य दिल्ली को दुनिया की सबसे स्वच्छ, हरित और पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी राजधानियों में शामिल करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जवाबदेही, पारदर्शिता और जनभागीदारी को मजबूत करने वाली प्रत्येक तकनीकी पहल दिल्ली को इस लक्ष्य के और करीब ले जाएगी।

दिल्ली सरकार के आंकड़ों के अनुसार, सड़क, मिट्टी और निर्माण गतिविधियों से उत्पन्न धूल राजधानी के वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। ग्रीष्म ऋतु में कुल वायु प्रदूषण में इसकी हिस्सेदारी लगभग 27 प्रतिशत और शीत ऋतु में 15 प्रतिशत तक रहती है। वहीं, पीएम-10 उत्सर्जन में धूल की हिस्सेदारी 66 प्रतिशत और पीएम-2.5 उत्सर्जन में लगभग 38 प्रतिशत है। इसी चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए डस्ट पोर्टल 2.0 विकसित किया गया है। डस्ट पोर्टल 2.0 में जीआईएस मैपिंग।

लाइव 360 डिग्री पीटीजेड कैमरे, पीएम-10 और पीएम-2.5 सेंसर, रियल-टाइम एनालिटिक्स और एआई आधारित मॉनिटरिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को शामिल किया गया है। यह पोर्टल निर्माण स्थलों की सटीक मैपिंग करेगा और धूल नियंत्रण से जुड़े पांच प्रमुख मानकों का स्वतः मूल्यांकन करेगा, जिससे निगरानी अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी और एकरूप होगी। साथ ही, यह निर्माण स्थलों के निकटतम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन (एक्यूएमएस) की पहचान कर साइट-स्तरीय डेटा का विश्लेषण करेगा। प्रदूषण का स्तर बढ़ते ही सिस्टम स्वतः येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी करेगा ताकि संबंधित एजेंसियां समय रहते आवश्यक कार्रवाई कर सकें।

पोर्टल के माध्यम से अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने और नियमों के उल्लंघन पर एनफोर्समेंट नोटिस स्वतः जारी करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिससे कागजी कार्यवाही कम होगी और कार्रवाई की गति तेज होगी। इसके अलावा, जिला-वार निगरानी, प्रदूषण के रुझानों और हॉटस्पॉट विश्लेषण के लिए व्यापक डैशबोर्ड उपलब्ध कराया गया है, जिससे सरकार और संबंधित विभाग डेटा-आधारित निर्णय ले सकेंगे।

दिल्ली लक्ष्मी योजना रक्षाबंधन से होगी शुरू, हर माह मिलेंगे 2500

नई दिल्ली,साहस समाचार।

दिल्ली सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली अपनी महत्वाकांक्षी योजना का नाम बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार आगामी 28 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर इस योजना का शुभारंभ कर सकती है। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में प्रतिमाह 2500 की आर्थिक सहायता भेजी जाएगी। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जाने वाली इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को नियमित वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना है। अनुमान है कि राजधानी की लगभग 17 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सकता है। विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने इस योजना का वादा किया था और अब सरकार इसके

क्रियान्वयन की दिशा में अंतिम तैयारियां कर रही है। योजना के लिए सरकार ने कुछ पात्रता संबंधी शर्तें भी निर्धारित की हैं। इसके अनुसार केवल 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं ही इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगी। लाभार्थी का कम से कम 10 वर्ष से दिल्ली का निवासी होना आवश्यक होगा। जिन महिलाओं के विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण दर्ज है, उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त केवल उन्हीं परिवारों की महिलाएं पात्र होंगी, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होगी।

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र महिलाओं को सरकार द्वारा तैयार किए जा रहे पंजीकरण माध्यम पर आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ आवश्यक अभिलेख जमा करने तथा पात्रता का सत्यापन पूरा होने के बाद प्रत्येक माह सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आवेदन के समय आधार संख्या, परिवार का आय प्रमाण-पत्र, बैंक खाते का विवरण तथा आधार से संबद्ध चल दूरभाष संख्या प्रस्तुत करनी होगी।

यमुना खादर में फिर बसीं हजारों झुग्गियां, बाढ़ से पहले बढ़ी प्रशासन की चिंता

नई दिल्ली,साहस समाचार।

दिल्ली के यमुना खादर क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बावजूद एक बार फिर बड़ी संख्या में झुग्गियां बस जाने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। अनुमान है कि खादर क्षेत्र में लगभग 10,000 लोग अवैध रूप से निवास कर रहे हैं। आगामी दिनों में यमुना के जलस्तर में वृद्धि की संभावना को देखते हुए प्रशासन को राहत एवं अस्थायी शिविरों की तैयारी करनी पड़ रही है, जिस पर हर वर्ष लाखों रुपये का व्यय होता है। गत वर्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मयूर विहार तथा पुराने लोहे के पुल के निकट स्थित अवैध झुग्गियों को हटाने के लिए व्यापक अभियान चलाया था।

इसके बावजूद खादर क्षेत्र में दोबारा बड़ी संख्या में लोगों के बस जाने से कार्रवाई की प्रभावशीलता पर प्रश्न उठने लगे हैं। स्थानीय स्तर पर यह आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि कुछ लोगों ने अधिकारियों की

मिलीभगत से दोबारा झुग्गियां खड़ी कर ली हैं। मयूर विहार, पुराने लोहे के पुल, कश्मीरी गेट, उस्मानपुर, सिग्नेचर पुल तथा बदरपुर खादर गांव के आसपास यमुना तटवर्ती क्षेत्रों में बड़ी संख्या में परिवार रह रहे हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण का कहना है कि अतिक्रमण के विरुद्ध समय-समय पर अभियान चलाया जाता है और जहां भी अवैध कब्जे पाए जाएंगे, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जानकारी के अनुसार खादर क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश लोग बिहार और उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। इनमें से कई परिवार सब्जी एवं फल विक्रय, कपड़ों की फेरी तथा अन्य छोटे-मोटे कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वे इन झुग्गियों में किराया देकर रह रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि यदि यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचता है तो खादर क्षेत्र को तत्काल खाली कराया जाएगा।

इसके लिए अस्थायी राहत शिविरों की व्यवस्था पहले ही सुनिश्चित की जा चुकी है, ताकि प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल समय-समय पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। स्थायी समाधान के लिए प्रभावी निगरानी, दोबारा अतिक्रमण रोकने की व्यवस्था तथा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की ठोस नीति आवश्यक है। अन्यथा हर वर्ष बाढ़ के मौसम में प्रशासन को राहत कार्यों पर भारी धनराशि खर्च करनी पड़ेगी और यमुना खादर में अवैध बसावट का सिलसिला जारी रहेगा।

धमाका पीड़ितों और आरोपी के अंतिम संस्कार की अनुमति

नई दिल्ली,साहस समाचार।

लालकिले के पास बीते साल नवंबर में हुए कार बम धमाके के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को अहम आदेश दिया। कोर्ट ने धमाके में मृत लोगों और आरोपी के जैविक अवशेषों के अंतिम संस्कार की अनुमति दे दी है। विशेष न्यायाधीश पीतांबर दत्त की अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को निर्देश दिया कि धमाके में मारे गए 11 पीड़ितों और मुख्य आरोपी उमर उन नबी के जैविक अवशेषों का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार या निस्तारण किया जाए। कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया कि सभी जैविक अवशेषों का निस्तारण मृतकों की धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए पूरी गरिमा के साथ किया जाए।

साथ ही एनआईए को इस प्रक्रिया के पालन की रिपोर्ट भी अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। सुनवाई के दौरान एनआईए ने अदालत को बताया कि मृतकों और आत्मघाती हमलावर के शरीर के अंगों से जुड़े सभी आवश्यक फोरेंसिक साक्ष्य पहले ही एकत्र कर लिए गए हैं। एजेंसी ने यह भी कहा कि लंबे समय से रखे होने के कारण ये अवशेष सड़ने लगे हैं, इसलिए इनके निस्तारण की अनुमति मांगी गई थी। गौरतलब है कि 10 नवंबर को हुए बम धमाके ने राजधानी को झकझोर दिया था। इस मामले में एनआईए ने 14 मई को 7500 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद पिछले महीने एजेंसी ने एक पूरक चार्जशीट भी दाखिल की, जिसमें तीन और आरोपियों को शामिल किया गया।

मुख्यमंत्री ने 70 लाख पौधा रोपण महाअभियान में लिया हिस्सा

नई दिल्ली,साहस समाचार।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को मॉडल टाउन में आयोजित 'एक पेड़ मां के नाम' – मिशन 70 लाख पौधा रोपण महाअभियान में हिस्सा लेकर पौधा रोपण किया। इस कार्यक्रम में मॉडल टाउन क्षेत्र में लगभग 1,100 पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक पौधा आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, हरियाली और स्वस्थ जीवन देने के संकल्प का प्रतीक है। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक अशोक गोयल, बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी, आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधि और अन्य नागरिक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने यहां आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में बड़े स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में पौधारोपण कार्यक्रम लगातार चलाए जा रहे हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 7 जुलाई को मेगा प्लांटेशन ड्राइव की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत

दिल्ली सरकार ने जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष पोर्टल - https://greendrive.delhivanmahotsav.in भी शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को पौधारोपण अभियान से जुड़ने और अपनी सुविधानुसार तिथि, समय और स्थान का चयन कर स्लॉट बुक करने की सुविधा दी गई है। दिल्ली सरकार वृक्ष रथ के माध्यम से आपके घर निःशुल्क पौधे पहुंचाएगी। साथ ही नागरिक नर्सरी लोकेटर के माध्यम से अपनी निकटतम सरकारी नर्सरी का चयन कर वहां से निःशुल्क पौधा भी प्राप्त कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी के प्रत्येक खाली और उपयुक्त स्थान को हरित क्षेत्र में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में मॉडल टाउन क्षेत्र में सेंट्रल वर्ज, मेट्रो कॉरिडोर के नीचे और सड़कों के दोनों ओर पौधारोपण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान केवल पौधे लगाने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रकृति, पर्यावरण और मातृत्व के प्रति सम्मान प्रकट करने का एक जनआंदोलन है। यह अभियान नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए दिल्ली को स्वच्छ, हरित और टिकाऊ भविष्य की ओर ले जा रहा है। उन्होंने दिल्लीवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे अधिक से अधिक संख्या में पौधारोपण करें और दिल्ली सरकार के 70 लाख पौधे लगाने के संकल्प को सफल बनाने में अपना योगदान दें।

बात मुद्दे की

आलोक गौड़

चुनावी वादे और खाली होता सरकारी खजाना!

नई दिल्ली। लोकतंत्र में चुनाव जनता का विश्वास जीतने के लिए लड़े जाते हैं, लेकिन यदि चुनाव जीतने का सबसे आसान तरीका सरकारी खजाना खोल देना बन जाए तो यह केवल राजनीतिक नहीं, आर्थिक चिंता का विषय भी है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को सुरक्षा देना है, लेकिन यदि कल्याणकारी योजनाएं चुनावी रणनीति का सबसे बड़ा हथियार बन जाएं, तो उनके दूरगामी परिणामों पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक हो जाता है। महाराष्ट्र पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की ताजा रिपोर्ट इसी असुविधाजनक प्रश्न को देश के सामने रखती है।

कैग के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में महाराष्ट्र का राजस्व घाटा 29,994 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। राजकोषीय घाटा 1.20 लाख करोड़ रुपये और कुल देनदारियां 8.6 लाख करोड़ रुपये दर्ज की गईं। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि मुख्यमंत्री माझी 'लाडकी बहन योजना' पर बढ़े भारी खर्च के कारण महिलाओं के कल्याण का बजट एक वर्ष में 261.7 करोड़ रुपये से बढ़कर 33,554.3 करोड़ रुपये हो गया। यह वृद्धि केवल एक आंकड़ा नहीं है। यह उस आर्थिक सोच का संकेत है जिसमें तत्काल राजनीतिक लाभ और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन बिगड़ने का खतरा दिखाई देता है।

यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि गरीब महिलाओं, किसानों, बुजुर्गों, दिव्यांगों और अन्य जरूरतमंद वर्गों के लिए सहायता योजनाएं किसी भी संवेदनशील सरकार का दायित्व हैं। किसी भी लोकतंत्र में सामाजिक सुरक्षा को गलत नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन सामाजिक सुरक्षा और चुनावी लोकलुभावन राजनीति में अंतर होता है। पहली व्यवस्था नागरिक को सम्मान के साथ खड़ा करने का प्रयास करती है, जबकि दूसरी कई बार मतदाता को तत्काल राहत देकर राजनीतिक लाभ सुनिश्चित करने का माध्यम बन जाती है।

सबसे बड़ा प्रश्न योजना का नहीं, उसकी वित्तीय क्षमता का है। क्या सरकारों ने यह आकलन किया कि इतनी बड़ी योजनाओं का खर्च अगले पांच या दस वर्षों तक कैसे उठाया जाएगा? क्या अतिरिक्त राजस्व का कोई स्थायी स्रोत तैयार किया गया? क्या यह पैसा विकास परियोजनाओं से हटाकर खर्च किया जाएगा या फिर कर्ज लेकर इसकी भरपाई होगी? यदि इन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर नहीं है, तो चिंता केवल अर्थशास्त्रियों की नहीं, आम नागरिक की भी होनी चाहिए।

कैग की रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण संकेत यही है कि सामाजिक क्षेत्र पर खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जबकि पूंजीगत व्यय का हिस्सा अपेक्षाकृत सीमित रहा। अर्थशास्त्र की सामान्य भाषा में इसका अर्थ यह है कि सरकार ने तत्काल खर्च पर अधिक ध्यान दिया, जबकि भविष्य की उत्पादन क्षमता बढ़ाने वाले निवेश पर अपेक्षाकृत कम। सड़कें, पुल, सिंचाई परियोजनाएं, औद्योगिक गलियारे, अस्पताल, सरकारी स्कूल, तकनीकी संस्थान और सार्वजनिक परिवहन है l यह सभी पूंजीगत निवेश के उदाहरण हैं। इन पर खर्च कम होने का असर तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ वर्षों बाद विकास की गति अवश्य प्रभावित होती है।

आज देश के लगभग सभी राज्यों में चुनावी राजनीति का स्वरूप बदल चुका है। घोषणापत्रों में रोजगार, औद्योगिक नीति, कृषि सुधार और प्रशासनिक सुधारों की चर्चा पहले होती थी। अब उनकी जगह मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, नकद सहायता, मुफ्त यात्रा, मुफ्त सिलेंडर और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसी घोषणाओं ने ले ली है। जनता को राहत मिलनी चाहिए, इसमें कोई विवाद नहीं। विवाद तब शुरू होता है जब राहत की जगह राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ले लेती है।

यह भी विडंबना है कि सत्ता पक्ष विपक्ष को 'रेवड़ी संस्कृति' का दोषी बताता है और सत्ता बदलते ही स्वयं उसी रास्ते पर चल पड़ता है। कांग्रेस हो, भाजपा हो या क्षेत्रीय दल l लगभग सभी चुनावी प्रतिस्पर्धा में इसी फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि समस्या किसी दल की नहीं, बल्कि राजनीति की बदलती प्रवृत्ति की है। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा आवश्यक है, लेकिन यदि वह आर्थिक अनुशासन को कमजोर करने लगे तो उसकी समीक्षा भी आवश्यक हो जाती है। लोकतंत्र में हर चुनाव के साथ एक नया घोषणापत्र आता है। उसमें जनता से वादे किए जाते हैं। यह स्वस्थ परंपरा है। लेकिन क्या कभी किसी राजनीतिक दल ने यह भी बताया कि जिन योजनाओं पर हजारों करोड़ रुपये खर्च होंगे, उनका पैसा आएगा कहां से? क्या कर बढ़ाए जाएंगे? क्या कर्ज लिया जाएगा? क्या दूसरे विकास कार्यों में कटौती होगी? या फिर आने वाली सरकारों और आने वाली पीढ़ियों पर यह बोझ छोड़ दिया जाएगा? यही वह सवाल है, जिससे देश की राजनीति लगातार बचती रही है।

विडंबना यह है कि चुनाव आयोग उम्मीदवारों के चुनावी खर्च पर तो कड़ी निगरानी रखता है, लेकिन राजनीतिक दलों के घोषणापत्र में किए गए हजारों करोड़ रुपये के वित्तीय वादों की व्यवहार्यता पर कोई स्वतंत्र व्यवस्था नहीं है। परिणाम यह है कि चुनावी प्रतिस्पर्धा धीरे-धीरे आर्थिक प्रतिस्पर्धा में बदलती जा रही है। एक दल यदि एक हजार रुपये देने का वादा करता है, तो दूसरा डेढ़ हजार का। तीसरा उससे भी अधिक। लेकिन कोई यह नहीं बताता कि यह पैसा आखिर आएगा कहां से।

महाराष्ट्र की कैग रिपोर्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने इसी आर्थिक असंतुलन की ओर संकेत किया है। यदि राजस्व व्यय लगातार बढ़ेगा और पूंजीगत निवेश घटेगा, तो विकास की गति पर असर पड़ना तय है। कर्ज लेकर कुछ समय तक योजनाएं चलाई जा सकती हैं, लेकिन कर्ज लेकर स्थायी समृद्धि नहीं बनाई जा सकती। आज लिया गया ऋण कल ब्याज सहित लौटाना ही पड़ता है। सरकारें बदलती हैं, लेकिन कर्ज नहीं बदलता।

पुलिस ने विफल की कारोबारी की हत्या की साजिश, दो शूटर गिरफ्तार

नई दिल्ली,साहस समाचार।

राजधानी में जबरन धन उगाही और सुनियोजित हत्याओं के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। उत्तरी जिला पुलिस की विशेष दल ने कुख्यात अपराधी हिमांशु उर्फ भाऊ गिरोह से जुड़े दो शूटरों को गिरफ्तार कर रोहिणी क्षेत्र के एक प्रमुख कारोबारी की हत्या की साजिश को समय रहते विफल कर दिया। गिरफ्तार आरोपियों में एक विधि-विवादित किशोर भी शामिल है। पुलिस ने उनके कब्जे से दो अवैध अर्धस्वचालित पिस्तौल तथा छह जीवित कारतूस बरामद किए हैं।

पुलिस के अनुसार विदेश में रहकर गिरोह का संचालन कर रहे हिमांशु उर्फ भाऊ ने मार्च माह में रोहिणी के एक प्रतिष्ठित कारोबारी से बड़ी रकम की रंगदारी मांगी थी। इस

संबंध में अमन विहार थाने में मामला दर्ज किया गया था। धमकी मिलने के बाद कारोबारी को सुरक्षा भी उपलब्ध कराई गई थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उसी कारोबारी की हत्या के उद्देश्य से गिरोह के स्थानीय सहयोगियों ने दोनों शूटरों को हथियार उपलब्ध कराकर हरियाणा से दिल्ली भेजा था।

उत्तरी जिला की अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त निहारिका भट्ट ने बताया कि विशेष दल को गुप्त सूचना मिली थी कि गिरोह के सदस्य नेहरू विहार क्षेत्र में पहुंचने वाले हैं और वहां से रोहिणी जाकर वारदात को अंजाम देंगे। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर 6 और 7 जुलाई की मध्यरात्रि दोनों संदिग्धों को दबोच लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से अवैध हथियार और कारतूस बरामद हुए। इसके बाद तिमारपुर थाने में शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हरियाणा के जींद जिले के मनोहरपुर गांव निवासी प्रदीप उर्फ काली (26) तथा फतेहाबाद जिले के एक किशोर के रूप में हुई है। पूछताछ में पता चला कि प्रदीप पहले बस परिचालक का कार्य करता था और बाद में एक मदिरा विक्रय केंद्र पर कार्यरत था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि किशोर आरोपी अपने एक परिचित के माध्यम से हिमांशु उर्फ भाऊ के संपर्क में आया था। उसे दूरभाष के माध्यम से दिल्ली में एक बड़े कारोबारी की हत्या करने का निर्देश दिया गया।

यात्रा के दौरान गिरोह के विभिन्न सहयोगियों ने अलग-अलग स्थानों पर दोनों आरोपियों को हथियार उपलब्ध कराए तथा लगातार उनके ठहरने और आने-जाने की व्यवस्था करते रहे। जांच के अनुसार आरोपियों को हरियाणा से अलग-अलग वाहनों के माध्यम से दिल्ली लाया गया। उन्हें नेहरू विहार क्षेत्र में अन्य सहयोगियों से मिलने और आगे की योजना के अनुसार लक्ष्य तक पहुंचने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि, इससे पहले ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया और पूरी साजिश को विफल कर दिया।

दिल्ली पुलिस अब इस मामले में शामिल स्थानीय सहयोगियों, हथियार उपलब्ध कराने वालों तथा अन्य फरार आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।

आईजीआई एयरपोर्ट पर 6.37 किलो गांजा जब्त, तीन यात्री गिरफ्तार

नई दिल्ली,साहस समाचार।

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट पर कस्टम्स अधिकारियों ने मादक पदार्थों की तस्करी के तीन अलग-अलग मामलों का पर्दाफाश करते हुए करीब 6.37 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किया है। इस संबंध में तीन यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है। बरामदगी विमान के शौचालयों, सीटों के नीचे और यात्रियों के सामान से की गई। अधिकारियों के अनुसार, हाइड्रोपोनिक वीड गांजे की एक उच्च क्षमता वाली किस्म होती है, जिसे मिट्टी के बजाय पोषक तत्वों से भरपूर पानी में उगाया जाता है।

पहले मामले में बैंकॉक से सोमवार को दिल्ली पहुंचे एक भारतीय यात्री को एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम (एपीआईएस) की प्रोफाइलिंग के आधार पर ग्रीन चैनल पार करने के बाद रोका गया। यात्री के सामान से कुछ संदिग्ध नहीं

मिला, लेकिन विमान की तलाशी लेने पर पिछले हिस्से के दोनों शौचालयों में छिपाए गए चार सीलबंद पैकेट बरामद हुए। इनमें करीब 3.47 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा होने का संदेह है। पूछताछ में यात्री ने इन्हें शौचालय में छिपाने की बात स्वीकार कर ली। जबकि दूसरे मामले में फुकेत से सोमवार को आए एक यात्री को भी एपीआईएस प्रोफाइलिंग के आधार पर रोका गया।

उसके सामान से कोई प्रतिबंधित वस्तु नहीं मिली। इसके बाद अधिकारियों ने विमान की तलाशी ली, जहां पंक्ति संख्या 12 की सीटों के नीचे छिपाए गए छह सीलबंद पैकेट मिले। इनमें करीब 1.5 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक गांजा था। बाद में यात्री ने विमान में पैकेट छिपाने की बात स्वीकार की। और तीसरे मामले में बैंकॉक से रविवार को दिल्ली पहुंची एक भारतीय यात्री को ग्रीन चैनल पार करने के बाद रोका गया। उसके सामान की एक्स-रे जांच में संदिग्ध तस्वीरें दिखाई दीं। तलाशी के दौरान दो वैक्यूम-सील पैकेट बरामद हुए, जिनमें लगभग 1.4 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक गांजा मिला।

कस्टम्स विभाग ने बताया कि तीनों मामलों में बरामद पदार्थ हरे रंग का एनडीपीएस पदार्थ है, जिसे प्रारंभिक जांच में गांजा या मारिजुआना माना जा रहा है। तीनों आरोपियों को मादक पदार्थ एवं मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 की धारा 43(बी) के तहत गिरफ्तार किया गया है, जबकि बरामद मादक पदार्थ और उसे छिपाने में इस्तेमाल सामग्री को धारा 43(ए) के तहत जब्त कर लिया गया है।

संपादकीय

सुप्रीम कोर्ट की गरिमा और न्याय की संवेदना

देश की सर्वोच्च अदालत केवल एक न्यायिक संस्था नहीं है, बल्कि संविधान की आत्मा और लोकतंत्र की अंतिम आशा का केंद्र है। जब देश का कोई नागरिक हर स्तर पर न्याय की तलाश में असफल होकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, तो उसके मन में यही विश्वास होता है कि यहां उसकी बात निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ सुनी जाएगी। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट की गरिमा, मर्यादा और प्रतिष्ठा पूरे न्यायिक तंत्र की आधारशिला मानी जाती है। अदालत की गरिमा बनाए रखना जितना न्यायाधीशों और न्यायिक कर्मचारियों का दायित्व है, उतना ही वहां उपस्थित प्रत्येक अधिवक्ता, याचिकाकर्ता और नागरिक का भी कर्तव्य है।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता वकील द्वारा न्यायाधीशों के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करना, कागजात उछालना और मुख्य न्यायाधीश के लिए अपशब्द कहना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। किसी भी परिस्थिति में न्यायालय के भीतर इस प्रकार का व्यवहार स्वीकार्य नहीं कहा जा सकता। अदालत तर्क और कानून की भाषा समझती है, आक्रोश और अपमान की नहीं। यदि न्याय की लड़ाई लड़ने वाला स्वयं कानून और शिष्टाचार की सीमाएं लांघने लगे, तो न्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास कमजोर होने का खतरा पैदा हो सकता है। वकील केवल अपने मुवक्किल का प्रतिनिधि नहीं होता, बल्कि वह न्यायालय का भी अधिकारी माना जाता है। उसकी वाणी, उसका आचरण और उसका व्यवहार न्यायपालिका की गरिमा से जुड़ा होता है। इसलिए अधिवक्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे कठिन से कठिन परिस्थिति में भी संयम बनाए रखें। असहमति व्यक्त करने का अधिकार सभी को है, लेकिन असहमति और अभद्रता के बीच एक स्पष्ट रेखा होती है। उस रेखा का सम्मान करना ही लोकतांत्रिक संस्कृति और न्यायिक परंपरा की पहचान है।

इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अदालत ने वकील की याचिका खारिज कर दी, लेकिन उसके खिलाफ अवमानना की कठोर कार्रवाई नहीं की। न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि वह व्यक्ति संभवतः अत्यधिक तनाव और मानसिक दबाव में है तथा उसकी हताशा स्पष्ट दिखाई दे रही है। यह दृष्टिकोण न्यायपालिका की मानवीय संवेदना को भी सामने लाता है। कानून केवल दंड देने का माध्यम नहीं है, बल्कि परिस्थितियों को समझने और न्याय के व्यापक उद्देश्य को ध्यान में रखने की व्यवस्था भी है।

वास्तविकता यह है कि न्याय की तलाश में अदालत तक पहुंचने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी पीड़ा, संघर्ष या अन्याय का बोझ लेकर आता है। वर्षों तक मुकदमे लड़ने, आर्थिक बोझ उठाने और बार-बार अदालतों के चक्कर लगाने के बाद जब अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता, तब कई लोग मानसिक रूप से टूट जाते हैं। यह टूटन कभी-कभी हताशा और असंतुलित व्यवहार के रूप में सामने आती है। इसका अर्थ यह नहीं कि ऐसे व्यवहार को उचित ठहराया जाए, बल्कि यह समझना आवश्यक है कि उसके पीछे पीड़ा और निराशा का एक लंबा इतिहास भी हो सकता है।

न्यायपालिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी निष्पक्षता के साथ-साथ उसकी संवेदनशीलता भी है। यदि कोई व्यक्ति अदालत में अत्यधिक तनावग्रस्त दिखाई देता है, तो उसके साथ कानून के अनुसार व्यवहार करते हुए उसकी मानसिक स्थिति को भी समझना चाहिए। न्याय केवल आदेश सुनाने से पूरा नहीं होता, बल्कि यह विश्वास भी पैदा करता है कि अदालत ने व्यक्ति की बात पूरी गंभीरता से सुनी और समझी। यही विश्वास लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूंजी है।

यह भी सच है कि न्याय में विलंब, लंबी कानूनी प्रक्रिया और बढ़ते मुकदमों का बोझ कई लोगों में निराशा पैदा करता है। ऐसे में न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ, सरल और समयबद्ध बनाने की दिशा में लगातार प्रयास आवश्यक हैं। जब लोगों को समय पर न्याय मिलेगा, तो निराशा और असंतोष की स्थितियां भी कम होंगी। न्याय व्यवस्था का उद्देश्य केवल विवादों का निपटारा नहीं, बल्कि समाज में विश्वास और संतुलन बनाए रखना भी है।

अन्न से ऊर्जा तक आत्मनिर्भर भारत की नई क्रांति का नाम है ई-20

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार ई20 लागू करने से पहले 40 हजार किलोमीटर से अधिक व्यापक परीक्षण किए गए। इन परीक्षणों में इंजन की कार्यक्षमता, रबर पार्ट्स, फ्यूल लाइन, धातु पर जंग, उत्सर्जन, ईंधन दक्षता और टिकाऊपन जैसे सभी पहलुओं की जांच की गई।

भारतीय इतिहास के सबसे कठिन अध्यायों में वर्ष 1965-66 का वह दौर गिना जाता है, जब देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, किंतु खेतों की पैदावार उतनी नहीं थी कि हर नागरिक का पेट भर सके। भारत को अमेरिका से पीएल-480 (PL-480) योजना के तहत गेहूं आयात करना पड़ता था। विदेशी जहाजों पर आने वाले अनाज का इंतजार करना उस समय की मजबूरी थी। तब शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि यही भारत कुछ दशकों बाद दुनिया के सबसे बड़े खाद्यान्न उत्पादक देशों में शामिल होगा और कई देशों को अनाज निर्यात भी करेगा।

अब प्रश्न यह है कि क्या यह परिवर्तन किसी चमत्कार से आया ? निश्चित ही नहीं, चमस्कार नहीं श्रम एवं वैज्ञानिक परिश्रम से अवश्य आया था। इसके पीछे वर्षों तक चले वैज्ञानिक अनुसंधान, दूरदर्शी नीतियां, किसानों का परिश्रम रहा है। आज भारत एक बार फिर उसी प्रकार के परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार चुनौती भोजन की न होकर ऊर्जा जरूरतों की है। फिलहाल देश का जो परिदृष्य है, वह पहले कभी खाद्यान्न के लिए विदेशों पर निर्भर रहने के समान ही मौजूद है। आज भी अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगभग 88 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करना पड़ रहा है। यही कारण है कि जब भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, उसका सीधा प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था, विदेशी मुद्रा भंडार और आम नागरिक की जेब पर पड़ता है।

ऐसे समय में ई20 अर्थात 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कहना होगा कि एक नया ईंधन भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की उस लंबी यात्रा का प्रारंभिक चरण है, जो आने वाले वर्षों में देश की आर्थिक और रणनीतिक स्थिति को बदल सकता है। दुर्भाग्य यह है कि जिस पहल को उसके व्यापक राष्ट्रीय संदर्भ में समझा जाना चाहिए, वह सोशल मीडिया पर फैली अधूरी जानकारियों और भ्रामक दावों के कारण विवाद का विषय बनती जा रही है।

भारतीय विकास यात्रा का इतिहास बताता है कि लगभग हर बड़े परिवर्तन का प्रारंभ संदेह और विरोध के बीच हुआ। जब हरित क्रांति शुरू हुई, तब भी अनेक विशेषज्ञों ने आशंका जताई थी कि नई किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक भारतीय खेती को नुकसान पहुंचाएंगे।

जब श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई तो यह कहा गया कि गांवों में संगठित दुग्ध उत्पादन संभव नहीं होगा। डिजिटल भुगतान प्रणाली आई तो अनेक लोगों ने इसे अव्यावहारिक बताया। आज यही भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल भुगतान नेटवर्क का संचालन कर रहा है।

इसी प्रकार एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर भी अनेक आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। कोई इसे पुराने वाहनों के लिए नुकसानदायक बता रहा है, कोई इसे इंजन

खराब करने वाला ईंधन कह रहा है, तो कोई इसे केवल सरकारी प्रयोग बताकर खारिज करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन यदि तथ्यों और वैज्ञानिक अध्ययनों पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है।

अक्सर ऐसा प्रचार किया जाता है कि भारत ने अचानक पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाने का निर्णय ले लिया, जबकि वास्तविकता यह है कि इस दिशा में काम वर्ष 2001 में ही शुरू हो गया था। सबसे पहले सीमित स्तर पर एथेनॉल मिश्रण का परीक्षण किया गया। वर्ष 2004 में इसे औपचारिक कार्यक्रम का स्वरूप मिला और 2006 तक कई राज्यों में पांच प्रतिशत मिश्रण वाला ईंधन उपलब्ध कराया जाने लगा,

उसके बाद भी सरकार ने जल्दबाजी नहीं दिखाई। लगभग दो दशकों तक उत्पादन क्षमता बढ़ाने, वैज्ञानिक परीक्षण करने, ऑटोमोबाइल कंपनियों से परामर्श लेने, नई डिस्टिलरियां स्थापित करने और किसानों को एथेनॉल उत्पादन से जोड़ने की दिशा में लगातार काम किया गया। वर्ष 2018 की राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति और 2021 में जारी ई20 रोडमैप इस पूरी प्रक्रिया के महत्वपूर्ण पड़ाव बने। यानी जिस निर्णय को आज लोग अचानक लागू हुई नीति समझ रहे हैं, उसके पीछे लगभग पच्चीस वर्षों की तैयारी, हजारों करोड़ रुपये का निवेश और हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, कृषि विशेषज्ञों तथा उद्योग जगत का साझा प्रयास है।

भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उद्योग बढ़ रहे हैं, वाहन बढ़ रहे हैं, सड़कें बढ़ रही हैं और ऊर्जा की मांग भी लगातार बढ़ रही है, किंतु इसके साथ एक बड़ी चुनौती भी जुड़ी हुई है, वह है कच्चे तेल का आयात। देश अपनी आवश्यकता का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। इसका अर्थ यह है कि पश्चिम एशिया में युद्ध हो, वैश्विक आपूर्ति बाधित हो या अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ जाएं, उसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। यही कारण है कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता आज राष्ट्रीय सुरक्षा का भी विषय बन चुकी है। यहीं से ई20 जैसी पहल का महत्व बढ़ जाता है। यदि पेट्रोल का 20 प्रतिशत हिस्सा भारत के खेतों से उत्पादित एथेनॉल से पूरा होने लगे तो विदेशी तेल पर निर्भरता धीरे-धीरे कम होगी। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी, किसानों को नया बाजार मिलेगा और ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा देश के भीतर ही तैयार होगा।

वास्तव में इस बात के लिए सभी को खुश होना चाहिए कि भारत के किसान दशकों से देश का पेट भरते आए हैं। अब पहली बार उन्हें ऊर्जा अर्थव्यवस्था का भी महत्वपूर्ण भागीदार बनाया जा रहा है। गन्ने के साथ-साथ मक्का, चावल और अन्य कृषि आधारित स्रोतों से बनने वाला एथेनॉल किसानों की आय का नया माध्यम बन रहा है। यह परिवर्तन ग्रामीण भारत को देश की ऊर्जा सुरक्षा से जोड़ने का प्रयास है। जिस प्रकार हरित क्रांति ने किसानों को खाद्यान्न उत्पादन का नायक बनाया था, उसी प्रकार एथेनॉल मिशन उन्हें ऊर्जा उत्पादन का भी सहभागी बना रहा है।

आज सूचना का सबसे बड़ा स्रोत सोशल मीडिया बन गया है, किंतु यही सबसे बड़ा भ्रम भी पैदा कर सकता है। किसी एक व्यक्ति का व्यक्तिगत अनुभव पूरे देश की वास्तविकता नहीं हो सकता। सार्वजनिक नीति का मूल्यांकन वैज्ञानिक परीक्षणों, संस्थागत अध्ययनों और व्यापक आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। ई20 को लेकर भी यही दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इसे किसी राजनीतिक बहस या सोशल मीडिया ट्रेंड के रूप में देखने के बजाय भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा नीति के रूप में समझना होगा। जिस प्रकार हरित क्रांति के परिणाम एक-दो वर्ष में नहीं दिखाई दिए थे, उसी प्रकार ऊर्जा आत्मनिर्भरता की यह यात्रा भी धैर्य, वैज्ञानिक सोच और निरंतर निवेश की मांग करती है।

ई20 को लेकर सबसे बड़ी आशंका यही व्यक्त की जाती है कि इससे पुराने वाहनों के इंजन खराब हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर ऐसे अनेक वीडियो और संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं जिनमें दावा किया जाता है कि एथेनॉल इंजन, रबर पाइप और फ्यूल सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जब इन दावों की तुलना वैज्ञानिक परीक्षणों और वास्तविक आंकड़ों से की जाती है तो तस्वीर अलग दिखाई देती है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार ई20 लागू करने से पहले 40 हजार किलोमीटर से अधिक व्यापक परीक्षण किए गए। इन परीक्षणों में इंजन की कार्यक्षमता, रबर पार्ट्स, फ्यूल लाइन, धातु पर जंग, उत्सर्जन, ईंधन दक्षता और टिकाऊपन जैसे सभी पहलुओं की जांच की गई। परीक्षणों में ऑटोमोबाइल उद्योग, अनुसंधान संस्थानों तथा तेल कंपनियों की भी सक्रिय भागीदारी रही। इतना ही नहीं, करोड़ों वाहनों की सर्विसिंग के दौरान भी ई20 के कारण इंजन खराब होने या बड़े स्तर पर तकनीकी समस्या के प्रमाण नहीं मिले। यदि वास्तव में यह ईंधन व्यापक रूप से नुकसानदायक होता तो वाहन कंपनियों के पास लाखों वारंटी क्लेम आते और पूरे ऑटोमोबाइल उद्योग में गंभीर संकट खड़ा हो जाता। ऐसा नहीं हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत अनुभव और वैज्ञानिक निष्कर्षों के बीच अंतर समझना आवश्यक है।

ई20 को लेकर दूसरा बड़ा तर्क माइलेज का दिया जाता है। सरकार स्वयं स्वीकार करती है कि कुछ वाहनों में तीन से पांच प्रतिशत तक माइलेज कम हो सकता है, किंतु क्या किसी ईंधन का मूल्यांकन केवल माइलेज के आधार पर किया जा सकता है? क्योंकि एथेनॉल की ऑक्टेन रेटिंग अधिक होती है। इससे इंजन में बेहतर दहन होता है, एंटी-नॉक क्षमता बढ़ती है, इंजन की कार्यक्षमता सुधरती है और प्रदूषण कम होता है। भविष्य में जैसे-जैसे वाहन निर्माता E20 को ध्यान में रखकर इंजन डिजाइन करेंगे, वैसे-वैसे प्रदर्शन और बेहतर होने की संभावना है। इसलिए E20 को केवल माइलेज के चश्मे से देखना उसके व्यापक लाभों की अनदेखी करना होगा।

आम नागरिक का यह प्रश्न पूरी तरह स्वाभाविक है कि यदि पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाया जा रहा है तो कीमत कम क्यों नहीं हुई? दरअसल, यह धारणा पूरी तरह सही नहीं कि एथेनॉल हमेशा पेट्रोल से सस्ता होता है। भारत में एथेनॉल की खरीद किसानों को उचित मूल्य देने की नीति के तहत की जाती है। इसके साथ परिवहन, भंडारण, गुणवत्ता परीक्षण और कर जैसे कई खर्च जुड़े होते हैं, इसलिए अनेक परिस्थितियों में इसकी वास्तविक लागत पेट्रोल के बराबर या उससे अधिक भी हो सकती है।

उत्तर प्रदेश, चुनाव और हिंदुत्व

मृत्युंजय दीक्षित

अयोध्या में श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद की आड़ में सभी रामद्रोही, श्रीराम को काल्पनिक मानने वाले, रामभक्तों पर गोलियां चलवाने वाले, श्रीराम जन्मभूमि पर अस्पताल और शौचालय बनवाने की बात करने वाले रामभक्त होने का स्वांग रच रहे हैं और सोच रहे हैं कि ऐसा करके वो 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को मात दे देंगे। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव, ज्योतिषपीठाधीश्वर तथाकथित शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से आशीर्वाद लेकर गो संरक्षण, सनातन पंरपराओं, सामाजिक सरोकारों व समसामयिक राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। सरस्वती से मिलने के बाद सपा मुखिया आक्रामक हैं और कहते हैं कि जो लोग भाजपा के साथ हैं वह रामघाती हैं। सपा मुखिया अपने ही जाल में फंसते दिख रहे हैं।

अखिलेश इस बार अपने आपको सनातनी दिखाने के लिए पत्नी सहित बड़े मंगल भंडारों में गए और हनुमान चालीसा का पाठ करते दिखाई दिए। यह उनके लिए दो नावों की सवारी जैसा है क्योंकि मुस्लिम तुष्टिकरण अभी भी उनकी प्रमुख रणनीति है। सपा मुखिया श्रीकृष्ण जन्मभूमि के प्रति मौन हो जाते हैं, क्योंकि इससे मुस्लिम वोट बैंक छिटकने का डर है । उनका सनातन प्रेम हिंदू समाज को बांटने की राजनीति ही है और इससे उनको अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना है। सपा मुखिया अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने हिंदुओं की आस्था के साथ इतने अधिक घृणित पाप किए हैं कि वह तथाकथित शंकराचार्य के चरणों में बैठकर भी नहीं धुलेंगे।

अभी चुनाव रैलियां शुरू होने में समय है इसलिए अखिलेश यादव राम मंदिर में चढ़ावा कांड से लेकर बद्रीनाथ धाम और मां बगलामुखी मंदिर से प्राप्त समाचारों को हवा देकर भाजपा को दबाव मे लेना चाहते हैं । उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तीखे तेवर अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि सनातन और हिंदुत्व की पिच उनकी अपनी है और यहां कोई उनको दबाव में नहीं ले सकता। योगी कहते हैं कि सपा ने हनुमानगढ़ी में हनुमान चालीसा पढ़वाने का पाप किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सनातन और हिंदुत्व को लेकर अत्यंत आक्रामक हैं। वो अखिलेश और सपा के पापों का पिटारा खोलकर हिंदू समाज को सावधान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने अयोध्या की जनसभा में कहा कि समाज के प्रत्येक तबके ने श्री रामजन्मभूमि की मुक्ति के लिए आंदोलन और संघर्ष किया जबकि सपा और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधाएं खड़ी कीं। जो लोग आज आस्था की बात करते हैं याद करिए इन लोगों ने हमारे पवित्र हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का काम किया था। आप कल्पना कीजिए कि क्या कोई जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा। क्या इनकी सरकारें करवा पाएंगी ?अगर नहीं तो अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया ?

योगी ने जनमानस को याद दिलाया कि लंबे समय तक अयोध्या अविकसित रही। पिछड़ी रही। सड़क, बिजली, पानी के लिए तरसती रही।

अयोध्या आने वाले श्रद्धालु मां सरयू का आशीर्वाद नहीं ले पाते थे। अयोध्या की जनसभा में उन्होंने नगर पंचायत खिरौनी का नामकरण मां ज्वाला जी के नाम से जबकि भदरसा को भरत नगर करने की घोषणा की। अयोध्या से योगी ने सपा व अन्य कालनेमियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि अब उन्हें, उन्हीं की भाषा में उत्तर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री का मानना है कि सपा व कांग्रेस को हिंदुओं की कोई चिंता नहीं है। ये पहला हक मुस्लिमों को देना चाहती हैं।

दरअसल चढ़ावा विवाद के बाद सपा व कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन के दल इसमें अपने लिए अवसर खोज रहे हैं जबकि उनके पूर्व कर्म इतने हिंदू द्रोही रहे हैं कि वह अपने ही जाल में फंस जाते हैं। जब उत्तर प्रदेश सहित भाजपा शासित अन्य राज्य सरकारें गोवध व तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहती हैं। इस पर यह लोग हल्ला मचाने लगते हैं। कोर्ट चले जाते हैं। वहीं आजकल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ मिलकर ये गौ माता की सुरक्षा व संरक्षा के प्रति चिंता जता रहे हैं। गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं। विडंबना यह है की इन्हीं शंकराचार्य ने यूपी में बूचड़खानों के बंद होने का विरोध किया था। यदि शंकराचार्य व सपाइयों को गौ माता की वास्तविक चिंता है तो वह अपनी यात्रा दक्षिण भारत में क्यों नहीं निकालते, जहां सबसे अधिक गोवध हो रहा है । भाजपा सरकार आने से पहले जब बंगाल से गोवध की वीभत्स तस्वीरें आ रही थी तब यह शंकराचार्य और सपाई क्यों नहीं बोले थे ? शंकराचार्य को यदि गौ संरक्षण करना है तो उन्हें पंजाब और झारखंड में भी अपनी यात्रा निकालनी चाहिए और बूचड़खानों की बंदी का स्वागत करना चाहिए।

वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर योगी कहते हैं कि सनातन आस्था पर प्रहार कर रहे इन दोनों दलों की खामोशी से गिरगिट भी शर्मशार हो जाएगा। वक्फ के नाम पर प्रदेश में हजारों हेक्टेयर जमीन बेची गई। वह सवाल करते हैं कि क्या उस पर सपा और कांग्रेस एक बार भी बोली? अभी जो सपा व कांग्रेस के लोग स्वयं को सनातनी साबित करने की होड़ मचाए हुए हैं, क्या यह लोग आगामी दिनों में कांवड़ यात्रियों पर पुष्पवर्षा करेंगे? विकृत मानसिकता वाले तथाकथित सेक्युलर दल कभी सनातनी बन जाते हैं कभी अच्छे हिंदू और बुरे हिंदू का विचार लेकर आ जाते हैं । वो कहते हैं कि जब अहमदाबाद उच्च न्यायालय ने 38 आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई तब सपा ,कांग्रेस व ओवैसी को वह फैसला रास नहीं आया । जब दक्षिण भारत के राजनीतिक दल विशेषकर तमिलनाडु से स्टालिन परिवार की ओर से हिंदू सनातन समाज की तुलना डेंगू व मलेरिया आदि बताकर उनके उन्मूलन की बात की जाती है तब इन लोगों के मुंह में ताला लग जाता है।

ऐसा लग रहा है कि हिंदू आस्था का अपमान करते-करते सपा पीडीए की राजनीति से भी दूर होती चली जा रही है। वास्तविकता यह है कि बंगाल में हिंदुत्व के उभार और ममता की पराजय के बाद से सपा नेता बुरी तरह से घबरा गए हैं। विपक्ष को 2027 में ममता दीदी से बहुत आस थी वह आस ध्वस्त हो चुकी है। अब ममता की पार्टी भी कंगाल हो चुकी है। यही कारण है कि अब सपा मुखिया अखिलेश यादव सनातनी चोला पहनकर अपनी चुनावी नैया पार लगाने की जुगत में हैं।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

देश में विकसित संस्कृति के विकास से बढ़ा आयकर का दायरा

किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था की पहचान उसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) या उद्योगों की वृद्धि के साथ ही इस बात से भी होती है कि उसके नागरिक आर्थिक रूप से कितने जागरूक, जिम्मेदार और अनुशासित हैं। आज भारत में आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की लगातार बढ़ती संख्या इसी सकारात्मक परिवर्तन की ओर संकेत कर रही है। निश्चित ही भारतीय जनसंख्या का यह कदम देश में विकसित होती वित्तीय संस्कृति, बढ़ती कर-अनुपालन की भावना और औपचारिक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते समाज का प्रतिबिंब है। आयकर विभाग द्वारा आकलन वर्ष 2026-27 के लिए अब तक 1.7 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल होने की जानकारी इस बदलाव का स्पष्ट प्रमाण है, जिसमेंकि एक ही दिन में 10 लाख से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए हैं। यह व्यवहार आर्थिक अनुशासन का परिचायक है और विकसित देशों की कर संस्कृति से मेल खाता है।

साथ ही भारत सरकार के उन प्रयासों को भी दर्शाता है, जिसमें कि भारत में पिछले एक दशक के दौरान कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए व्यापक सुधार किए गए हैं। ई-फाइलिंग पोर्टल, प्री-फिल्ड रिटर्न, आधार-पैन एकीकरण, ऑनलाइन सत्यापन, फेसलेस असेसमेंट और त्वरित रिफंड जैसी व्यवस्थाओं ने करदाताओं की कठिनाइयों को काफी कम किया है। अब आईटीआर दाखिल करना पहले की तुलना में कहीं अधिक सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक हो गया है। यही कारण है कि पहले जो लोग आयकर प्रक्रिया से दूरी बनाए रखते थे, वे भी अब औपचारिक कर व्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं।

वस्तुतः आज भारत सरकार द्वारा नए आईटीआर फॉर्म में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, शेयर बायबैक से होने वाले नुकसान और कुछ प्रकार के ट्रेडिंग लेनदेन के संबंध में अतिरिक्त जानकारी अनिवार्य किए जाने से यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। इससे कर चोरी की संभावनाएं कम होंगी और ईमानदार करदाताओं के लिए व्यवस्था अधिक विश्वसनीय बनेगी।

कहना होगा कि आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में वृद्धि का सीधा प्रभाव प्रत्यक्ष कर संग्रह पर भी दिखाई दे रहा है। वित्त वर्ष 2026-27 की प्रारंभिक अवधि में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 14.64 प्रतिशत और सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 12.46 प्रतिशत की वृद्धि यह बताती है कि भारत की अर्थव्यवस्था का औपचारिक दायरा लगातार विस्तृत हो रहा है। प्रत्यक्ष कर किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे स्वस्थ राजस्व स्रोत माने जाते हैं, क्योंकि वे आय और लाभ पर आधारित होते हैं तथा आर्थिक गतिविधियों की वास्तविक स्थिति को भी प्रतिबिंबित करते हैं। यह परिवर्तन वस्तुतः इस बात का भी प्रमाण है कि भारतीय समाज में वित्तीय साक्षरता भी तेजी से बढ़ी है। डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई, ऑनलाइन निवेश, म्यूचुअल फंड, बीमा, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और पूंजी बाजार में बढ़ती भागीदारी ने नागरिकों को अपनी आय और निवेश का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखने के लिए प्रेरित किया है। आज युवाओं के लिए आयकर रिटर्न भरना केवल कर भुगतान का माध्यम नहीं, बल्कि उनकी वित्तीय पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। बैंक ऋण, गृह ऋण, शिक्षा ऋण, वीजा, सरकारी निविदाओं तथा अनेक वित्तीय प्रक्रियाओं में आईटीआर की उपयोगिता लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि अनेक ऐसे लोग भी नियमित रूप से रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, जिनकी कर देनदारी सीमित या शून्य है।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), डिजिटल भुगतान प्रणाली, जनधन-आधार-मोबाइल (जैम) ढांचा, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), औपचारिक रोजगार में वृद्धि और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार ने भी कर आधार को व्यापक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नकदी आधारित लेनदेन की जगह डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग से आर्थिक गतिविधियों का दस्तावेजीकरण मजबूत हुआ है, जिससे कर प्रशासन अधिक प्रभावी बना है। इस बढ़त के कारण से देश का राजस्व मजबूत हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसका सीधा संबंध देश के विकास से है।

चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में नए मानक स्थापित कर रहा है भारत : राजनाथ सिंह

लखनऊ, एजेंसी।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में भारत नए मानक स्थापित कर रहा है और साथ ही देश में जीन थेरेपी, परमाणु चिकित्सा तथा अन्य आधुनिक प्रौद्योगिकियों के माध्यम से वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों के लिए स्वदेशी समाधान विकसित किए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) के 22वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि भारत की स्वास्थ्य प्रणाली पहले की तुलना में अधिक आत्मनिर्भर, सुलभ, किफायती, आधुनिक और जन-केंद्रित बनकर उभरी है।

लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने कहा, आज भारत जीन थेरेपी, परमाणु चिकित्सा और अन्य आधुनिक प्रौद्योगिकियों के माध्यम से वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों के लिए स्वदेशी समाधान विकसित कर रहा है। चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में देश नए मानक स्थापित कर रहा है।

उन्होंने कहा कि केजीएमयू ने देश को अनेक ऐसे चिकित्सक दिए हैं, जिन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और डॉ. बी. सी. रॉय पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया गया है। इस संस्थान से जुड़े लोगों ने सेवा, समर्पण और संवेदनशीलता की अद्वितीय मिसाल पेश की है। रक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति प्रोफेसर डॉ. सरोज चूरामणि गोपाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने वर्ष 2024 में 79 वर्ष की आयु में पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश लिया। उन्होंने कहा, इससे यह संदेश मिलता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सिंह ने कहा कि सरकार केवल उपचार पर ही नहीं, बल्कि रोगों की रोकथाम पर भी विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि सीएआर-टी (चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी-सेल) थेरेपी कैंसर के उपचार में अत्यंत उपयोगी साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि पहले लोगों को इलाज के लिए अपनी संपत्ति तक बेचनी पड़ती थी, लेकिन अब 'आयुष्मान भारत' योजना के तहत पात्र लोगों को मुफ्त उपचार की सुविधा मिल रही है। रक्षा मंत्री ने कहा, "पिछले 12 वर्षों में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार का लक्ष्य केवल चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था विकसित करना है जो सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण हो। उन्होंने अंगदान को मानवता के लिए 'सबसे बड़ा उपहार' बताते हुए कहा कि आज भी समाज में इसे लेकर अनेक भ्रांतियां और झिझक हैं, जिन्हें दूर करने में चिकित्सकों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

सिंह ने कहा, हमारे वैज्ञानिकों ने हीमोफीलिया के उपचार के लिए स्वदेशी जीन थेरेपी का सफल प्रदर्शन किया है। वहीं, पुणे के एक संस्थान के वैज्ञानिकों ने स्तन कैंसर के उपचार के लिए अत्याधुनिक नैनो मेडिसिन विकसित की है।

उन्होंने कहा कि तीन दशक बाद वर्ष 2024 में भारत में पेनिसिलिन-जी का उत्पादन दोबारा शुरू हुआ है। साथ ही, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना ने चिकित्सा उपकरणों के स्वदेशी विनिर्माण को नयी गति प्रदान की है।

रक्षा मंत्री ने बताया कि देशभर में 19,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को गुणवत्तापूर्ण दवाएं अत्यंत किफायती दरों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।

चिकित्सा पेशे से जुड़े लोगों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, चिकित्सक अत्यधिक तनावपूर्ण वातावरण में कार्य करते हैं, जिसका उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए उन्हें अपने स्वास्थ्य की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

ऋतब्रत को और समय न दिया जाए: ममता

नई दिल्ली, एजेंसी। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि पार्टी के प्रतिद्वंद्वी गुट के नेता ऋतबत बनर्जी को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और संगठनात्मक चुनावों से जुड़े दावों पर जवाब देने के लिए और समय नहीं दिया जाना चाहिए।

पार्टी के भीतर जारी विवाद दो जुलाई को उस समय और गहरा गया था, जब ऋतब्रत के नेतृत्व वाले गुट ने खुद को असली अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) बताते हुए निर्वाचन आयोग का रुख किया। इस गुट ने कहा था कि उसने 22 जून को आयोजित विशेष अधिवेशन के बाद आयोग को इसकी जानकारी दी थी और संगठन में किए गए कथित बदलावों को मान्यता देने का अनुरोध किया था। इस दावे के बाद निर्वाचन आयोग ने ममता बनर्जी और ऋतब्रत बनर्जी, दोनों को पत्र भेजकर अपना-अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने छह जुलाई को अपना जवाब दाखिल कर दिया, जबकि ऋतब्रत बनर्जी के गुट को जवाब दाखिल करने के लिए 10 जुलाई की शाम साढ़े पांच बजे तक का अतिरिक्त समय दिया गया। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 12 जुलाई को निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में कहा, 10 जुलाई बीत जाने और उसके बाद करीब दो दिन गुजर जाने के बावजूद ऋतब्रत बनर्जी की ओर से इस संबंध में कोई जवाब हमें नहीं भेजा गया है।

राकांपा प्रमुख के रूप में सुनेत्रा पवार के चयन को चुनौती

मुंबई, एजेंसी।

महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की अध्यक्ष चुने जाने को पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने चुनौती दी है। उन्होंने कानूनी नोटिस जारी कर संगठनात्मक चुनाव नए सिरे से कराने की मांग की है।

दिल्ली स्थित विधि फर्म एआरएस एसोसिएट्स ने राकांपा के राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह की ओर से नौ जुलाई को यह कानूनी नोटिस जारी किया। इसमें दावा किया गया है कि 26 फरवरी को हुआ चुनाव असंवैधानिक था और इसे अमान्य घोषित किया जाना चाहिए।

यह नोटिस सुनेत्रा पवार, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और महासचिव बृजमोहन श्रीवास्तव को संबोधित है। इसमें आरोप लगाया गया है कि चुनाव प्रक्रिया राकांपा के संविधान के अनिवार्य प्रावधानों का पालन किए बिना तथा प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को विधिवत सूचना दिए बिना शुरू की गई।

नोटिस के अनुसार, तत्कालीन राकांपा अध्यक्ष अजित पवार के 28 जनवरी को निधन के बाद पार्टी ने निर्वाचन आयोग को सूचित किया था कि नए अध्यक्ष के चुनाव तक प्रफुल्ल पटेल कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे।

बीजेपी राजनीतिक दलों को तोड़ रही: दीपेन्द्र हुड्डा

गुरुग्राम,एजेंसी। सांसद दीपेन्द्र सिंह हुड्डा ने रविवार को संत कबीर शिरोमणि सम्मान समारोह में भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर राजनीतिक दलों को तोड़ने का काम कर रही है। साथ ही कहा कि कांग्रेस सरकार के समय मिलेनियम सिटी के रूप में पहचान बनाने वाले गुरुग्राम को भाजपा ने एक बारिश में डूबने वाले शहर की पहचान दे दी है। समारोह में संत कबीर को दीपेन्द्र हुड्डा ने नमन किया।

उन्होंने ने आरोप लगाया कि भाजपा लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। भाजपा ने विभिन्न राज्यों में राजनीतिक दलों को तोड़ने का काम किया है। हरियाणा में भी पिछले 12 वर्षों से हर वर्ग की उपेक्षा की गई है।

बिहार में सब्सिडी वाली हेली पर्यटन सेवा शुरू : सम्राट

पटना, एजेंसी।

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के चुनिंदा पर्यटन स्थलों के लिए आम लोगों को किफायती हवाई पर्यटन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सोमवार को 'बिहार हेली पर्यटन एवं एयर पर्यटन सेवा योजना-2026' की शुरुआत की।

राजधानी पटना में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की। योजना के तहत सोमवार से टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है, जबकि हेलीकॉप्टर सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को संचालित होगी।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य बिहार को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान दिलाना है।

इस योजना के तहत पटना से राजगीर, वाल्मीकिनगर और कैमूर के लिए सब्सिडी आधारित हेली पर्यटन सेवा शुरू की गई है। सरकार प्रत्येक टिकट पर अधिकतम 15,422 रुपये तक की सब्सिडी देगी, जिससे आम लोग कम खर्च में हवाई पर्यटन का अनुभव ले सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र के विस्तार से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही होमस्टे, स्थानीय हस्तशिल्प और ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा।

सपा के लोग गठबंधन को लेकर ईमानदार नहीं : इमरान मसूद

नई दिल्ली, एजेंसी।

कांग्रेस के लोकसभा सदस्य इमरान मसूद ने सोमवार को समाजवादी पार्टी (सपा) पर मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर खामोश रहने का आरोप लगाया और कहा कि यदि अखिलेश यादव की पार्टी को आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिये कांग्रेस से गठबंधन करना है, तो ईमानदारी से करना चाहिए।

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से सांसद ने कहा, समाजवादी पार्टी के नेता लगातार मुझ पर हमला करते रहते हैं। मुझ पर निशाना साधने से क्या मिलेगा? उन्हें इसके बजाय भाजपा का मुकाबला करना चाहिए।

मसूद ने दावा किया, मुसलमानों की मस्जिदें टूट रहीं हैं, मदरसे टूट रहे हैं, मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है और दलितों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। इन मुद्दों पर भी बोलना चाहिए। लेकिन वे (सपा नेता) ऐसा नहीं करेंगे। इसके बजाय वे मुझे ही निशाना बनाते हैं।

उन्होंने कहा, सपा के लोग गठबंधन की बात करते हैं। अगर आप सचमुच भाजपा से लड़ना चाहते हैं, तो गठबंधन को अंतिम रूप दीजिए...ईमानदारी से करिये। अगर आप धरातल पर कुछ करना ही नहीं चाहते, तो इसका मतलब है कि आप ईमानदार नहीं हैं। उन्होंने कहा, अगर (विपक्ष की) सरकार नहीं आई, तो मिटना तो हमें (मुस्लिम) पड़ेगा।

बाघ के डर से जलाशय में कूदे पिता-पुत्र की मौत

नागपुर,एजेंसी। महाराष्ट्र के नागपुर जिले की रामटेक तहसील के देवलापार वन क्षेत्र में एक व्यक्ति और उसके सात वर्षीय बेटे की बाघ के डर से अपनी जान बचाने की कोशिश के दौरान डूबने से मौत हो गई।

वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, मृतकों की पहचान दुलारा गांव के निवासी 35 वर्षीय जीवन धर्मराज कोकोडे और उनके सात वर्षीय बेटे जतिन जीवन कोकोडे के रूप में हुई है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, जीवन रविवार सुबह अपने बेटे और साले के साथ छावरी गांव के पास लखन बांध पर मछली पकड़ने गया था। इसी दौरान उनके साले ने एक बाघ को तेजी से अपनी ओर आते देखा और शोर मचाकर उन्हें सचेत करने का प्रयास किया।

असम की मतदाता सूचियों में 91,385 संदिग्ध मतदाता: हिमंत

गुवाहाटी, एजेंसी।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने सोमवार को विधानसभा में बताया कि राज्य की मतदाता सूचियों में अभी 91,000 से अधिक 'डी-वोटर' (संदिग्ध मतदाता) हैं।

कांग्रेस विधायक नूरुल इस्लाम के एक सवाल का जवाब देते हुए शर्मा ने कहा कि कुल 91,385 संदिग्ध मतदाताओं में से सर्वाधिक सोनितपुर में हैं और यह संख्या 13,719 है। बारपेटा में 8,081 संदिग्ध मतदाता हैं, जबकि उदलगुड़ी और नागांव में भी मतदाता सूचियों में ऐसे मतदाताओं की संख्या 7,800 से अधिक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, विवादित या संदिग्ध नागरिकता प्रमाण-पत्र वाले मतदाताओं के नाम के आगे 'डी' अक्षर अंकित करने की प्रक्रिया राज्य में 1997 से लागू है।

'डी' मतदाता की अवधारणा 1997 में निर्वाचन आयोग द्वारा असम में शुरू की गई थी। आयोग ने उन लोगों की सूची तैयार की थी, जो अपनी भारतीय नागरिकता के पक्ष में पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके थे। यह व्यवस्था देश में असम के अलावा कहीं और लागू नहीं है।

गृह और राजनीतिक विभाग के मंत्री तौर पर जवाब देते हुए शर्मा ने कहा कि 56,728 'डी' मतदाताओं को विदेशी (नागरिक संबंधी) अधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किया गया, जबकि उनमें से उच्च न्यायालय में अपील करने वाले 831 लोगों को अदालत ने भी विदेशी करार दिया।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा, 65,171 'डी' मतदाताओं को इन अधिकरणों ने भारतीय नागरिक घोषित किया, जबकि गुवाहाटी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने क्रमशः 42 और 3 'डी' मतदाताओं को देश का वैध नागरिक घोषित किया। कांग्रेस के वाजिद अली चौधरी के एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए शर्मा ने कहा कि वर्ष 1997 में जब पहली बार यह प्रक्रिया शुरू की गई थी, तब राज्य में 'डी' मतदाताओं की संख्या 1,99,596 थी।

उन्होंने बताया कि अब तक 'डी' मतदाताओं से जुड़े 2,44,144 मामले विदेशी (नागरिक संबंधी) अधिकरणों को भेजे गए हैं, जिनमें से 2,05,659 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है और 56,728 लोगों को विदेशी घोषित किया गया है।

संदिग्ध मतदाताओं से जुड़े मामलों के अलावा, सीमा पुलिस द्वारा अब तक 1,90,657 अन्य मामले भी इन अधिकरणों को भेजे गए हैं। इनमें से 1,55,490 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है और 1,15,945 लोगों को विदेशी नागरिक घोषित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशी घोषित किये गए इन लोगों में से 31,789 को निर्वासित किया जा चुका है।

सार समाचार

कर्नाटक में विधानसभा सत्र से पहले कैबिनेट विस्तार के संकेत

बेंगलुरु,एजेंसी। कर्नाटक कैबिनेट विस्तार को लेकर महीनों से बना राजनीतिक सस्पेंस खत्म करते हुए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोमवार को संकेत दिया कि छह अगस्त से शुरू हो रहे राज्य विधायिका के मानसून सत्र से पहले यह प्रक्रिया पूरी हो जायेगी। इसके लिए नयी दिल्ली दौरे के बाद कांग्रेस आलाकमान से निर्णायक हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। उपमुख्यमंत्री का यह बयान अब तक का सबसे स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस नेतृत्व इस राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दे को सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसने मंत्री पद के आकांक्षी सत्ताधारी दल के विधायकों के बीच लॉबिंग, अटकलों और बेसब्री को बढ़ा दिया था।

समान नागरिक संहिता का अंतिम प्रतिवेदन मुख्यमंत्री को सौंपा

भोपाल,एजेंसी। मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को तीन खंडों में तैयार अंतिम प्रतिवेदन सौंप दिया। मुख्यमंत्री ने निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा करने पर समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का आभार व्यक्त किया। प्रतिवेदन सौंपने के दौरान समिति के सदस्य प्रो. गोपाल शर्मा, बुधपाल सिंह, शोभा पैठणकर तथा सदस्य सचिव अजय कटेसरिया उपस्थित थे।

राज्य सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार प्रतिवेदन के पहले खंड में समिति की अनुशंसाएं शामिल हैं।

भारत की अर्थव्यवस्था का विकास इंजन बन चुका है उत्तर प्रदेश : योगी

लखनऊ, एजेंसी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं रह गया है, बल्कि यह भारत की अर्थव्यवस्था का विकास इंजन बन चुका है।

उन्होंने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य में 50,000-60,000 करोड़ रुपये की सड़क अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें उत्तर-दक्षिण संपर्क को मजबूत करने वाली योजनाएं भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने 4,850 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए कहा, आज गडकरी जी ने 50,000-60,000 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल, गंगा, बुंदेलखंड, आगरा-लखनऊ और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से पहले से ही बेहतर पूर्व-पश्चिम संपर्क है, लेकिन अब उत्तर-दक्षिण संपर्क को मजबूत करने के लिए नए क्षेत्रों की पहचान की गई है। आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने पांच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए बाईपास और प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय को चार लेन सड़क से जोड़ने की योजनाओं को भी मंजूरी दी है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार जताते हुए कहा कि इन मंजूरियों से उत्तर प्रदेश का सड़क नेटवर्क और मजबूत होगा तथा आर्थिक विकास को और गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में उत्तर प्रदेश में उल्लेखनीय बदलाव आया है।

उन्होंने कहा, दस वर्ष पहले उत्तर प्रदेश पहचान के संकट से जूझ रहा था। न तो कोई नीति थी और न ही दिशा। प्रदेश दंगों और माफिया राज के लिए जाना जाता था तथा बीमारू राज्यों में गिना जाता था।

योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं रह गया है, बल्कि यह भारत की अर्थव्यवस्था का विकास इंजन बन चुका है।

उन्होंने इस बदलाव का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सुशासन, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे का मॉडल बनकर उभरा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब सड़क, रेल, मेट्रो, हवाई अड्डों और अंतर्देशीय जलमार्गों से जुड़ा एकीकृत परिवहन नेटवर्क विकसित हो चुका है।

सड़क हादसे की आड़ में की गई हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार

रुद्रपुर,एजेंसी। उत्तराखंड में ऊधम सिंह नगर जिले के जसपुर में सड़क दुर्घटना के नाम पर की गई हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बलेनो कार भी बरामद कर ली है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने जानबूझकर मोटरसाइकिल को कार से टक्कर मारकर घटना को अंजाम दिया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के अनुसार गत 10 जुलाई को डायल-112 के माध्यम से सूचना मिली कि ठाकुरद्वारा चुंगी के पास खेड़ा रोड पर एक कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी है और कार चालक मौके से फरार हो गया है।

राजनीतिक रैलियों में बच्चों के इस्तेमाल पर नोटिस जारी करे ओएससीपीसीआर: बीजद

भुवनेश्वर, एजेंसी।

बीजद ने सोमवार को ओडिशा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (ओएससीपीसीआर) से मांग की कि वह 12 जुलाई को भुवनेश्वर में आयोजित एक राजनीतिक रैली में कथित रूप से नाबालिग बच्चों को शामिल किये जाने के मामले में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और अन्य लोगों को 'कारण बताओ नोटिस' जारी करे।

ओएससीपीसीआर को दिए गए एक ज्ञापन में, बीजू जनता दल (बीजद) ने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल और पूर्व विधायक प्रभात बिस्वाल भी इसी मामले में बराबर के जिम्मेदार थे। बीजद ने दावा किया कि जब बिस्वाल यहां भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में माझी और सामल की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए तो रैली में बड़ी संख्या में बच्चे भाजपा की तख्तियां लिये हुए नजर आए। भाजपा कार्यालय जाते समय, बिस्वाल और उनके समर्थकों ने मास्टर कैंटीन चौक से राम मंदिर चौक तक एक जुलूस निकाला, जिसमें केसरिया टोपी पहने बच्चे भी शामिल हुए और उन्होंने सत्ताधारी पार्टी के समर्थन में नारे भी लगाए। बीजद प्रतिनिधिमंडल की सदस्य सुमित्रा जेना ने कहा, "बच्चों को राजनीतिक रैलियों में शामिल करना एक गंभीर मामला है क्योंकि इससे बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा को खतरा होता है। हमने ओएससीपीसीआर को एक ज्ञापन सौंपा है ताकि इस मामले की जांच की जा सके।

दतिया उपचुनाव : भाजपा, कांग्रेस के उम्मीदवारों ने दाखिल किए नामांकन

दतिया, एजेंसी।

मध्यप्रदेश में दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन सोमवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी और विपक्षी कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने नामांकन दाखिल किए।

कलेक्टर कार्यालय में तिवारी के नामांकन के अवसर पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी महेन्द्र सिंह और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहे जबकि कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह के नामांकन के दौरान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, भांडेर से विधायक फूल सिंह बरैया और दतिया जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक दांगी उपस्थित थे।

नामांकन के इस अवसर पर दोनों दलों ने अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए जनसभाओं का आयोजन किया और दतिया की जनता से अपने-अपने दलों के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जीत दिलाने की अपील की।

नामांकन के बाद किला चौक पर आयोजित जनसभा में भाजपा उम्मीदवार तिवारी ने नरोत्तम मिश्रा को बड़ा भाई और अभिभावक करार दिया तो मिश्रा ने रुंधे गले से कहा कि वह तिवारी की जीत तय करने के लिए दतिया के घर-घर में शीश झुकाएंगे।

राज्य में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में सात लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 29 अन्य घायल हुए हैं

बाढ़, भूस्खलन से अरुणाचल के कई जिलों में आम जनजीवन प्रभावित

ईटानगर, एजेंसी।

अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से सोमवार को कई जिलों में आम जनजीवन प्रभावित हुआ।

एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि सड़क संपर्क बाधित होने और सार्वजनिक ढांचे को नुकसान पहुंचने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बयान के मुताबिक, राज्य में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में सात लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 29 अन्य घायल हुए हैं। इसमें कहा गया है कि 26 जिलों के 425 गांवों में 97,182 लोग बाढ़ की चपेट में हैं। बयान के अनुसार, बाढ़ और भूस्खलन से कृषि और सार्वजनिक ढांचे को व्यापक नुकसान पहुंचा है। इसमें कहा गया है कि कुल 541.75 हेक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जबकि करीब 1,010 हेक्टेयर वन क्षेत्र को भी नुकसान पहुंचा है।

बयान में कहा गया है कि राज्य में 150 सड़कों, 19 पुलों, 21 पुलिया, 221 जलापूर्ति प्रणालियों, 58 सरकारी भवनों, 156 बिजली लाइनों, 224 बिजली खंभों, 10 पनबिजली परियोजनाओं, दो अस्पतालों और तीन स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा राज्यभर में सैकड़ों मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं।

राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (एसईओसी) ने बताया कि सोमवार तड़के ऊपरी क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण कुमे नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे कुरुंग कुमे जिले के परसी-पारलो सर्किल और डामिन उपखंड में भारी नुकसान हुआ। एसईओसी के मुताबिक, डामिन उपखंड में हुरी और डामिन को जोड़ने वाला पुल बह गया, जिससे सड़क संपर्क टूट गया। वहीं, परसी-पारलो सर्किल में एक आंगनवाड़ी केंद्र पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि एक निरीक्षण बंगले, चावल मिल, गिरजाघर, प्रार्थना-स्थलों और अन्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को भी काफी नुकसान पहुंचा और पगाम गांव को जोड़ने वाला पुल बह गया।

बाढ़ की वजह से इलाके के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान सेंट थॉमस स्कूल को भी व्यापक नुकसान पहुंचा है। इसमें कहा गया कि पूरा स्कूल परिसर जलमग्न हो गया, जिससे इमारतों, कक्षाओं, शिक्षण सामग्री, फर्नीचर, उपकरणों और शिक्षकों के आवास को क्षति पहुंची और शैक्षणिक गतिविधियां रोकनी पड़ीं।

अचानक आई बाढ़ से परिवहन व्यवस्था, सार्वजनिक ढांचे और आवासीय संपत्तियों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। जिला प्रशासन नुकसान का आकलन करने और राहत कार्यों के लिए अर्धसैनिक बलों, पुलिस तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहा है। अतिरिक्त उपायुक्त नबम ताजिक ने बताया कि हुरी सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में शामिल है, जहां 66 मीटर लंबा एक पुल बह गया।

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन पुल की मरम्मत के लिए सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के साथ मिलकर काम कर रहा है और इस कार्य में लगभग दो हफ्ते लगने की उम्मीद है।

देहरादून साइंस सिटी बनेगी विज्ञान और नवाचार का राष्ट्रीय केंद्र: धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देहरादून साइंस सिटी का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है

देहरादून, एजेंसी।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को देहरादून में राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) में साइंस सिटी परियोजना के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति परिसंवाद कार्यक्रम में भी हिस्सा किया। धामी ने कहा कि देहरादून साइंस सिटी का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। आने वाले वर्षों में ये साइंस सिटी केवल उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि पूरे देश के विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के लिए विज्ञान, नवाचार और अनुसंधान का अग्रणी केंद्र बनकर उभरेगी। उन्होंने कहा कि इस साइंस सिटी में हमारे युवाओं को अत्याधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध होंगी, जो उनके सपनों और विचारों को नई उड़ान देने का कार्य करेंगी।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 'विज्ञान सेतु' परिकल्पना के अंतर्गत सामुदायिक विज्ञान रेडियो 'विज्ञान वाणी' (88.8 मेगाहर्ट्ज), 'विज्ञान दृश्यम' तथा 'विज्ञान धारा' का लोकार्पण करते हुए कहा कि इन प्रयासों से प्रयोगशालाओं के जटिल ज्ञान को उत्तराखंड के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश में हरेला सप्ताह मनाया जा रहा है। हरेला केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी आस्था, पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारे दायित्व का प्रतीक पर्व भी है। उन्होंने कहा कि आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय संकट की चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे समय में हरेला पर्व पूरी दुनिया को ये संदेश देता है कि विकास और प्रकृति साथ-साथ चल सकते हैं।

धामी ने कहा कि आज पूरी दुनिया एक अभूतपूर्व तकनीकी बदलाव के दौर से गुजर रही है। अब रोबोट्स कारखानों से लेकर अस्पतालों तक में काम कर रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) इंसानी क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। वहीं, डेटा साइंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और बायो-टेक्नोलॉजी जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियां आज दुनिया की दिशा और दशा तय कर रही हैं। ऐसे समय में, हमें इस बदलाव को न केवल स्वीकार करना है, बल्कि इसका नेतृत्व भी करना है।

उन्होंने कहा कि आज देश के कई राज्य उत्तराखंड को कई क्षेत्रों में बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में देख रहे हैं। सिलल्यारा टनल में फंसे श्रमिकों का सुरक्षित निकालने का अभियान इसमें शामिल है। जिसे ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में पेश किया गया। इसीलिए सरकार ने अब से हर वर्ष 28 नवंबर को आपदा प्रबंधन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं में अद्भुत प्रतिभा और मेधा है। इसलिए अब हमें प्रदेश में ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है जहाँ हमारी इस युवा प्रतिभा को सही दिशा मिले ताकि वे वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के सामने ₹विकसित भारत 2047₹ का जो 'अमृत संकल्प' रखा है, उसकी सबसे मजबूत आधारशिला विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान ही है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने 'जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान' के नारे में 'जय अनुसंधान' जोड़कर देश के वैज्ञानिकों और युवाओं को एक नया मंत्र दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में देश डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और नेशनल क्वांटम मिशन जैसे बड़े अभियानों के साथ आगे बढ़ रहा है। उनके प्रयासों से भारत में अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है।

बागडे ने घर-घर जाने और सर्वे कर टीबी मुक्त राजस्थान का किया आह्वान

जयपुर, एजेंसी।

राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे ने टीबी मुक्त राजस्थान के लिए पंचायतवार प्रभावी निगरानी किये जाने के निर्देश दिये हैं। बागडे सोमवार को लोकभवन में टीबी उन्मूलन के लिए जनभागीदारी को और सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप समाज के हर वर्ग को साथ लेकर, इस बीमारी के प्रति फैले डर और भेदभाव को दूर किया जाये। उन्होंने आंकड़ों में नहीं व्यवहार में हरेक मरीज पर ध्यान देने पर जोर दिया तथा कहा कि टीबी को पूरी तरह से खत्म किया जाये।

इसके लिए उन्होंने हरेक गांव में घर घर जाने और टीबी मरीजों को वास्तविक रूप में चिन्हित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गांवों में टीबी मुक्त करने के प्रयासों हेतु ग्राम सेवकों को जवाबदेह बनाया जाये।

उन्होंने कहा कि कागज में नहीं वस्तुस्थिति में टीबी रोगियों को रोग मुक्त करने के प्रयास होने चाहिए। उन्होंने टीबी रोगियों के समग्र इलाज और बाद में पोषण पर भी विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि टीबी मुक्त करने के लिए मन से प्रयास हों। उन्होंने जिला कलेक्टर स्तर पर टीबी मरीजों का पता लगाने और उनके प्रभावी निदान के लिए जागरूकता के अधिकाधिक कार्य किए जाने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि मरीज गोद लेकर कार्य किये जाने के आंकड़ों की वास्तविकता का भी पता लगाया जाये। राज्यपाल ने इससे पहले टीबी रोगी परिवार को निक्षय मित्र कीट का वितरण किया। इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि सभी विभागों की सहभागिता से राजस्थान को टीबी मुक्त करने के लिए निरंतर प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2030 तक राजस्थान को पूरी तरह से टीबी मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राजस्थान में टीबी मुक्त अभियान के अंतर्गत 90 प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण किये जा चुके हैं। इसके तहत 11 हजार 143 अधिक जोखिम वाले गांवों का सर्वे कर 9 हजार 719 गांवों में विशेष शिविर लगाकर टीबी मुक्त राजस्थान के लिए कार्यवाही की गयी है। खींवसर ने बताया कि देश में सर्वाधिक एक्सरे स्क्रीनिंग राजस्थान में की गयी है। इसी से हमारी 95 प्रतिशत ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त हो गयी है। इस मौके मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि विश्वभर में टीबी के खिलाफ लड़ाई में भारत के प्रयास आज रॉल मॉडल है।

सार समाचार

पत्थरों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली ऑटो पर पलटी, तीन की मौत

मुरैना,एजेंसी। मध्यप्रदेश में मुरैना जिले के माता बसैया थाना क्षेत्र में सोमवार को पत्थरों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली के ऑटो पर पलट जाने से तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए। घायलों में दो की हालत गंभीर बताई गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार हादसा पाराशर की पुलिया के पास उस समय हुआ, जब माता बसैया से दर्शन कर ऑटो में सवार आठ लोग अपने गांव विजयपुरा लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद खंडा-पत्थरों से लदी ट्रॉली अनियंत्रित होकर ऑटो के ऊपर पलट गई, जिससे उसमें सवार लोग पत्थरों के नीचे दब गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य चलाकर घायलों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने महेंद्र राठौर, मनोरमा राठौर तथा ऑटो चालक रामकेश कुशवाह (निवासी बानमोर) को मृत घोषित कर दिया।

दतिया उपचुनाव में भावुक हुए नरोत्तम मिश्रा

दतिया,एजेंसी। मध्यप्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के नामांकन के अवसर पर पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा भावुक हो गए और कहा कि पार्टी ने उन्हें 30 वर्ष विधायक तथा 15 वर्ष मंत्री बनाकर सम्मान दिया है। अब उनका एकमात्र लक्ष्य भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को विजयी बनाना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि वह पार्टी से कुछ मांगने नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उन्हें जीवन में सब कुछ दिया है और अब वह पूरी निष्ठा से आशुतोष तिवारी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्य करेंगे।

चलती ट्रेन से तीन करोड़ रुपये का गोल्ड चोरी प्रकरण का खुलासा

जयपुर,एजेंसी। राजस्थान की झुंझुनूं जिला पुलिस और हरियाणा पुलिस की विशेष अनुसंधान टीम (एसआईटी) ने चलती ट्रेन से तीन करोड़ रुपये के सोने के जेवरात चोरी होने की सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए नवलगढ़ इलाके से तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर जमीन में गाड़कर छिपाया गया करीब दो करोड़ रुपये मूल्य का भारी मात्रा में सोना बरामद कर लिया है। झुंझुनू जिला पुलिस अधीक्षक कावेन्द्र सिंह सागर ने हरियाणा में घटित इस संवेदनशील और बड़ी चोरी की वारदात को गंभीरता से लेते हुए झुंझुनूं जिले की नवलगढ़ पुलिस को त्वरित कार्रवाई और आरोपियों की धरपकड़ के विशेष निर्देश दिये थे। यह वारदात गत 10 जून को घटित हुई थी। करौली जिले के बड़ागांव निवासी नरेंद्र सिंह गुर्जर भटिंडा की एक प्राइवेट लॉजिस्टिक फर्म में सोने के गहनों की डिलीवरी का काम करता है।

सेमी कंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनेगा मप्र : मोहन यादव

भोपाल, एजेंसी।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि 'एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य उच्च-विकास वाले प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निवेश की गति को तीव्र करना है, जिससे प्रदेश को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी), डेटा सेंटर एवं सेमी कंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में देश के अग्रणी और सबसे भरोसेमंद निवेश गंतव्यों में स्थापित किया जा सके।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को भोपाल के निजी होटल में आयोजित 'एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 : जीसीसी, डेटा सेंटर एवं सेमी कंडक्टर' के विशेष सत्र में देश-विदेश की 10 प्रतिष्ठित संस्थाओं के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों और उद्योगपतियों के साथ वन-टू-वन चर्चा कर रहे थे। उन्होंने इस महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान राज्य में निवेश को बढ़ावा देने, नई परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन

और भविष्य के रणनीतिक सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार से संवाद किया। बैठक में विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रमुखों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तकनीकी अवसंरचना और अनुसंधान एवं विकास से जुड़े अपने भावी प्रस्ताव एवं परियोजनाओं का खाका प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आर्सेनल इन्फो सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद पटानी और डायरेक्टर अमित खरे, फुजियामा पावर के संयुक्त प्रबंध निदेशक पवन कुमार गर्ग व प्लांट हेड नवीन सिन्हा तथा ओसेल डिवाइसेज लिमिटेड के संचालन प्रमुख रितेश कुमार के साथ निवेश पर चर्चा की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और डेटा सेंटर के विकास के लिए न्योबोल्ट लिमिटेट-एबीएआईडीसी के निदेशक राजेश वेत्चा और अंकित खुराना व सिद्धार्थ बाहुजा ने भी अपने प्रस्ताव रखे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एनवीडिया के रणनीतिक एवं व्यवसाय निदेशक गणेश महाबाला के साथ मध्य प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, डिजिटल नवाचार तथा भविष्य की तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की।

तकनीकी अवसंरचना और कैपेबिलिटी सेंटर्स को बढ़ावा देने के लिए सबमर इंडिया प्रायवेट लिमिटेड के अनुपम श्रीवास्तव और जेएसएम डाटाक्रॉप प्रायवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विकास गुप्ता और उत्कर्ष दुबे ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के समक्ष अपनी भावी परियोजनाओं का खाका प्रस्तुत किया।

होशियारपुर में 300 से अधिक लोग हिरासत में, 3.5 किग्रा हेरोइन बरामद

होशियारपुर,एजेंसी। पंजाब पुलिस के नशा तस्करों, गैंगस्टरों और संगठित अपराध के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत होशियारपुर पुलिस ने सोमवार को 'ऑपरेशन प्रहार 3.0' के दौरान जिलेभर में व्यापक कार्रवाई करते हुए 300 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया, कई वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया तथा करीब 3.5 किलोग्राम हेरोइन बरामद की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मलिक ने बताया कि यह अभियान पंजाब सरकार और पुलिस महानिदेशक गौरव यादव के निर्देशों पर चलाये जा रहे राज्यव्यापी अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य गैंगस्टरों, संगठित अपराधी गिरोहों, नशा तस्करों और भगोड़े अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है। उन्होंने बताया कि सोमवार तड़के से जिलेभर में 60 से अधिक पुलिस टीमों ने राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों, यूनिट इंचार्जों और पुलिस चौकी प्रभारियों के नेतृत्व में संदिग्ध ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की।

श्री बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी का आरोपी चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में

देहरादून, एजेंसी।

उत्तराखंड के चमोली जनपद स्थित श्री बदरीनाथ धाम में थाली भेंट की धनराशि में हुई वित्तीय अनियमितता के मामले में गिरफ्तार मंदिर समिति के एक कार्मिक को अदालत ने सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। चमोली पुलिस ने आज आरोपी प्रमोद नौटियाल को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) एवं प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोशीमठ हीना कौसर की अदालत में पेश किया। न्यायालय ने मामले से संबंधित विधिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए। श्री बदरीनाथ धाम में लोगों की आस्था से जुड़े इस संवेदनशील प्रकरण में शासन द्वारा इसका गंभीरतापूर्वक संज्ञान लिया गया। तत्पश्चात आठ जुलाई को युद्धवीर पुष्पवान, प्रभारी मंदिर अधिकारी, श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) ने पुलिस कोतवाली श्री बद्रीनाथ में लिखित तहरीर दी कि दो जुलाई को मंदिर में थाली भेंट गणना के दौरान वित्तीय अनियमितता की सूचना प्राप्त होने के आदेशानुसार विभागीय जांच समिति गठित की गई।

प्राथमिक जांच में प्रथम दृष्टया मंदिर समिति के कार्मिक प्रमोद नौटियाल द्वारा थाली भेंट गणना स्थल से मंदिर की धनराशि एवं अन्य भेंट सामग्री को अवैध रूप से अपने निजी हित में ले जाने की पुष्टि हुई है।

नक्सल मामलों की त्वरित समीक्षा कर पात्र लोगों को मिलेगी राहत: विजय शर्मा

रायपुर, एजेंसी।

छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने सोमवार को कहा कि नक्सल प्रकरणों में जेल में निरुद्ध लोगों के मामलों की शीघ्र एवं न्यायसंगत समीक्षा कर पात्र मामलों में विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शर्मा ने विधानसभा परिसर में बस्तर क्षेत्र से आए जनप्रतिनिधियों, नक्सल प्रकरणों में निरुद्ध लोगों के परिजनों, नक्सल पीड़ितों और युवाओं से मुलाकात कर उनके मामलों पर चर्चा की।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने और लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि 10 जुलाई को मंत्रालय में गृह विभाग के प्रमुख सचिव, संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर संभाग के सभी 12 जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में लंबित मामलों की समीक्षा कर

कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके तहत प्रकरणों को जनहानि वाले और जनहानि रहित मामलों में विभाजित किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में जनहानि नहीं हुई है, उनकी समीक्षा संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक प्रत्येक सप्ताह अभियोजन अधिकारियों और शासकीय अधिवक्ताओं के साथ करेंगे, ताकि पात्र लोगों को शीघ्र राहत मिल सके। वहीं जनहानि वाले लंबित मामलों में चालान प्रस्तुत करने, गवाहों की पेशी और न्यायिक प्रक्रिया को गति देने के निर्देश दिए गए हैं। शर्मा ने कहा कि यदि किसी अभियुक्त के परिजन अपने मामले की समीक्षा कराना चाहते हैं तो वे संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक को आवेदन दे सकते हैं।

सोलन में ढहा कांग्रेस का गढ़, जिला परिषद पर भाजपा का कब्जा

सोलन,एजेंसी। हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को सोलन जिला परिषद चुनाव में शानदार जीत दर्ज की और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों पदों पर अपना कब्जा मजबूत कर लिया। वरिष्ठ भाजपा नेता शीला कुमारी को जिला परिषद अध्यक्ष चुना गया है, जबकि उनकी पार्टी के सहयोगी पंकज शर्मा ने उपाध्यक्ष पद पर आसान जीत दर्ज की है। शीला कुमारी पहले भी जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में सफल कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं और उनके पास इस पद का व्यापक प्रशासनिक अनुभव है।

सत्रह सदस्यीय सोलन जिला परिषद में 10 सीटों के साथ भाजपा के पास पहले से ही स्पष्ट बहुमत था, जिससे आज का मतदान महज औपचारिकता बनकर रह गया है। कांग्रेस के लिए यह राजनीतिक बदलाव बेहद नाजुक मोड़ पर आया है।

सभी सदर अस्पतालों में गर्भवती माताओं एवं नवजात शिशुओं के लिए बनेगा आधुनिक सी-विंग: डॉ. अंसारी

रांची, एजेंसी।

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने राज्य की माताओं और नवजात शिशुओं को समर्पित एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा करते हुए कहा कि राज्य के सभी सदर अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के लिए अत्याधुनिक ₹सी-विंग (मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल)₹ विकसित किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य सुरक्षित मातृत्व, गुणवत्तापूर्ण प्रसव सेवाएं तथा नवजात शिशुओं की बेहतर चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करना है। डॉ. अंसारी ने कहा कि लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या और सरकारी अस्पतालों पर बढ़ते जनविश्वास को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

पहले जहां बड़ी संख्या में लोग निजी अस्पतालों की ओर रुख करते थे, वहीं अब झारखंड की जनता का भरोसा सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर लगातार बढ़ा है। यह स्वास्थ्य विभाग के लिए गर्व की बात है और इसी

विश्वास को और मजबूत बनाने के लिए सरकार लगातार नई पहल कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार मां और बहनों के सम्मान तथा उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।

गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पहले, प्रसव के दौरान और प्रसव के बाद एक ही परिसर में सभी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इन अस्पतालों में विशेषज्ञ स्त्री एवं प्रसूति रोग चिकित्सक, शिशु रोग विशेषज्ञ, प्रशिक्षित नर्सें, आधुनिक लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर, नवजात गहन चिकित्सा इकाई (एसएनसीयू) तथा आवश्यक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध होंगे।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सी-विंग (मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल) के निर्माण की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसका उद्देश्य प्रत्येक जिले में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप विकसित करना है, ताकि किसी भी गर्भवती महिला को बेहतर इलाज के लिए दूसरे जिले या निजी अस्पतालों का सहारा न लेना पड़े। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य केवल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना नहीं, बल्कि स्वस्थ परिवार, सुरक्षित मातृत्व, स्वस्थ बचपन और सशक्त झारखंड का निर्माण करना है।

जब एक मां सुरक्षित होगी, तभी एक स्वस्थ समाज और मजबूत राष्ट्र का निर्माण होगा। डॉ. अंसारी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में वर्षों से चली आ रही कमियों को दूर करने के लिए लगातार सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।

सरकार अस्पतालों की आधारभूत संरचना को मजबूत करने, डॉक्टरों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति, आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता तथा मरीजों को गुणवत्तापूर्ण और सम्मानजनक उपचार उपलब्ध कराने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में झारखंड की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था देश की सबसे भरोसेमंद व्यवस्थाओं में शामिल होगी और हर मां तथा हर नवजात शिशु को सुरक्षित, सम्मानजनक एवं आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नन्दन जैन ने दुर्दांत नक्सली हिड़मा के महिमामण्डन पर साधा कांग्रेस पर निशाना

नक्सलियों की संरक्षक है कांग्रेस : भाजपा

रायपुर एजेंसी।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नन्दन जैन ने कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव द्वारा दुर्दांत नक्सली कमांडर हिड़मा का महिमामण्डन किए जाने पर बेहद कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। आज सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय (कुशाभाऊ ठाकरे परिसर) में आयोजित पत्रकारवार्ता को सम्बोधित करते हुए जैन ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि यह कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस का नक्सल प्रेम खुलकर सामने आया है। कांग्रेस का इतिहास हमेशा से नक्सलियों के संरक्षण और उन्हें खाद-पानी देने का रहा है।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नंदन जैन ने कहा कि हजारों निर्दोष

आदिवासियों, आम नागरिकों और देश के वीर जवानों के खून से जिसके हाथ रंगे हैं, उस खूँखार नक्सली हिड़मा का महिमामण्डन करना कांग्रेस की विकृत मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव का यह कृत्य बस्तर के शहीदों और उनके परिवारों का घोर अपमान है। इसके लिए उन्हें और उनकी पार्टी को देश से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। श्री जैन ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और नक्सलियों का 'भाईचारा' दशकों पुराना है।

जब-जब देश में नक्सलियों पर कड़ा प्रहार होता है, तब-तब कांग्रेस नेताओं का दर्द छलक उठता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और वरिष्ठ नेता राजबब्बर जैसे बड़े कांग्रेसी नेता समय-समय पर नक्सलियों के पक्ष में खुलकर बयानबाजी करते रहे हैं। राजबब्बर ने तो नक्सलियों को 'क्रांतिकारी' तक कह दिया था। खुद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी हिड़मा जैसे राष्ट्रविरोधी तत्वों का महिमामण्डन कर चुके हैं, जो उनके देशविरोधी एजेंडे को साफ उजागर करता है। जैन ने कहा कि संसद पर हमला करने वाले अफ़ज़ल गुरु के लिए जिनकी सहानुभूति हो, उनके नेताओं के लिए माओवादी और नक्सलवादी "आदर्श" बन जाएँ तो हैरानी कैसी? कांग्रेस का राजनीतिक चरित्र अब किसी से छिपा नहीं है। देश पहले या वोट बैंक पहले— जवाब जनता अच्छी तरह जानती है। जैन ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में नक्सलियों के वैचारिक आकाओं को पालने-पोषने का काम किया गया। इसी कड़ी में अमर्त्य सेन जैसे चेहरों को व्यवस्था में ऊँचा ओहदा देकर नवाजा गया, जो नक्सलियों की 'वैचारिक ढाल' बनकर काम करते थे। आज जब केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के नेतृत्व में सुरक्षाबल नक्सलियों को उनके मांद में घुसकर ढेर कर रहे हैं, तो कांग्रेस नेतृत्व पूरी तरह बौखला गया है। अपने अस्तित्व को खतरे में देख कांग्रेस अब हिड़मा जैसे दुर्दांत अपराधियों के सहारे अपनी राजनीति चमकाना चाहती है। जैन ने कहा कि कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव अपने इस देशविरोधी और शर्मनाक बयान के लिए तुरंत बस्तर की जनता, जवानों के परिवारों और पूरे देश से बिना शर्त माफी मांगें।

हरियाणा में बनेगा वाहन स्क्रैपिंग पोर्टल ईवी चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार पर जोर

चंडीगढ़, एजेंसी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को स्क्रैप किये गये वाहनों के पंजीकरण और वैज्ञानिक निपटान के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने के निर्देश दिये हैं।

उन्होंने कहा कि इससे निजी और सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनेगी।

साथ ही राज्यभर में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना में तेजी लाने के भी निर्देश दिये। मुख्यमंत्री सोमवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में 'अर्जुन एसपीवी' की दूसरी बोर्ड बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

बैठक में हरियाणा स्वच्छ वायु सतत विकास परियोजना की वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना की समीक्षा की गयी। बैठक में गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में इलेक्ट्रिक बस सेवाओं के विस्तार, बस डिपो, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तथा पीपीपी मॉडल के तहत 200 नयी इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की तैयारियों पर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने फसल अवशेष प्रबंधन, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छ वायु से जुड़ी सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिये।

बैठक में एआई आधारित वायु गुणवत्ता प्रबंधन, राज्य उत्सर्जन सूची, निर्णय सहायता प्रणाली, वायु गुणवत्ता निगरानी और विभिन्न विभागों के बीच डेटा साझाकरण तंत्र को मजबूत बनाने पर भी चर्चा हुई।

यानिक सिनर ने जीता विंबलडन पुरुष एकल का खिताब

ज्वेरेव के खिलाफ यह सिनर की लगातार 10वीं जीत रही। वह विंबलडन पुरुष एकल के खिताब का बचाव करने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए हैं।

नई दिल्ली,एजेंसी। यानिक सिनर विंबलडन के पुरुष एकल का खिताब लगातार दूसरी बार जीतने में सफल रहे हैं। सिनर ने फाइनल मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4 से हराया। सिनर ने अपने करियर में यह पांचवां ग्रैंड स्लैम जीता है। ज्वेरेव के खिलाफ यह सिनर की लगातार 10वीं जीत रही। वह विंबलडन पुरुष एकल के खिताब का बचाव करने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए हैं। विंबलडन 2026 के खिताबी मुकाबले का पहला सेट बेहद रोमांचक रहा। सिनर और ज्वेरेव के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिली और मुकाबला टाई ब्रेकर तक पहुंचा।

अपने दमदार फोरहैंड शॉट के बूते ज्वेरेव टाई ब्रेकर को अपने नाम करने में सफल रहे। दूसरे सेट में सिनर ने वापसी की और स्कोर को एक-एक सेट की बराबरी पर ला दिया। यह सेट भी टाई ब्रेकर तक पहुंचा, लेकिन अंत में सिनर इस सेट में बाजी मारने में सफल रहे। तीसरे सेट में ज्वेरेव को पहला ब्रेक प्वाइंट मिला। हालांकि, इसी दौरान ज्वेरेव सिनर के ड्रॉप शॉट पर फिसलकर कोर्ट पर गिर पड़े, जिसके चलते वह अपने दाहिने घुटने को पकड़कर दर्द से कराहते नजर आए। गनीमत यह रही कि इलाज के बाद ज्वेरेव फिर से कोर्ट पर लौट आए और उन्होंने सिनर से कड़ा मुकाबला किया।

तीसरे सेट में सिनर बेहतरीन लय में दिखाई दिए और उन्होंने सेट को 6-3 से अपने नाम किया। चौथे सेट में सिनर ज्वेरेव की सर्विस तोड़ने में सफल रहे और उन्होंने मुकाबले में 4-3 की बढ़त बनाई। इसके बाद सिनर ने ज्वेरेव को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया और सेट को 6-4 से जीतने के साथ ही विंबलडन 2026 के पुरुष एकल का खिताब अपने नाम कर लिया।

जीत के बाद सिनर बेहद खुश दिखाई दिए और उन्होंने अपनी जीत का जमकर जश्न मनाया। तीसरे सेट में चोटिल होने का असर ज्वेरेव के खेल में साफतौर पर नजर आया। वह कोर्ट पर संघर्ष करते हुए दिखाई दिए। सिनर ने पिछले साल कार्लोस अल्काराज को हराकर विंबलडन 2025 के खिताब पर कब्जा जमाया था। इटली के स्टार टेनिस खिलाड़ी जानिक सिनर ने विंबलडन 2026 के पुरुष एकल का खिताब जीतने के बाद कहा कि हर ग्रैंड स्लैम की अपनी अलग कहानी और महत्व होता है, लेकिन इस बार की जीत उनके लिए बेहद खास है।

उन्होंने माना कि फ्रेंच ओपन में मिली हार के बाद विंबलडन जीतना आसान नहीं था, इसलिए इस सफलता की खुशी और भी ज्यादा है। फाइनल मुकाबले में सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4 से हराकर लगातार दूसरा विंबलडन खिताब अपने नाम किया। करीब तीन घंटे 46 मिनट तक चले इस मुकाबले में दोनों खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया, लेकिन अहम मौकों पर सिनर ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिनर ने कहा कि हर ग्रैंड स्लैम का माहौल, चुनौती और अनुभव अलग होता है।

उनके लिए यह खिताब इसलिए भी खास है क्योंकि फ्रेंच ओपन में मिली निराशा के बाद उन्होंने खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाया।

भारतीय महिला टीम की लॉर्ड्स में ऐतिहासिक जीत

लंदन,एजेंसी। स्नेह राणा (42 रन पर चार विकेट) की अगुवाई में गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन से भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड को लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र टेस्ट के चौथे और आखिरी दिन सोमवार को 270 रन के बड़े अंतर से रौंद दिया। भारत ने इंग्लैंड के सामने 457 रन का लक्ष्य रखा था। इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में छह विकेट पर 130 रन से आगे खेलते हुए 186 रन पर सिमट गयी। जो होना ही था, वो हो गया! लॉर्ड्स को अपना पहला महिला टेस्ट होस्ट करने में 142 साल लग गए, और भारतीय टीम ने इस मौके को यादगार बनाते हुए इंग्लैंड महिला को इस मशहूर जगह पर 270 रन से हरा दिया।

हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी आराम से बेहतर टीम थी, उन्होंने घरेलू मैदान पर इंग्लैंड को आउट-बैटिंग, आउट-बॉलिंग और आउट-फील्डिंग दी। रेड-बॉल क्रिकेट में भारत का दबदबा जारी है, पिछले 11 टेस्ट में सात जीत, तीन ड्रॉ और सिर्फ एक हार मिली है। यह इंग्लैंड में भारत का 11वां टेस्ट भी था, और वे देश में इस फॉर्मेट में बिना हारे हैं। जहां तक मैच की बात है, इंडिया ने शुरू से ही दबदबा बनाया। इंग्लैंड के सीमर्स को पहले दिन नई बॉल पर कंट्रोल बनाने में दिक्कत हुई, और स्मृति मंधाना ने इसका पूरा फायदा उठाया।

हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने भी फिफ्टी लगाईं, जिससे भारत ने अपनी पहली इनिंग में 285 रन बनाए। क्रांति गौड़ ने फिर पांच विकेट लेकर लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर अपना नाम दर्ज कराया और इंग्लैंड को 170 रन पर ऑल आउट कर दिया। पहली पारी में 115 रन की बढ़त के साथ, भारत ने दूसरी पारी में अपनी पकड़ मजबूत कर ली।

मंधाना ने 83 रन के बाद 70 रन बनाए, जिसके बाद यास्तिका भाटिया ने 113 रन बनाये और फिर ऋचा घोष ने 52 गेंदों में नाबाद 50 रन बनाकर इंग्लैंड के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। 457 रन के मुश्किल टारगेट का पीछा करते हुए, इंग्लैंड एक बार फिर बल्ले से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया और 186 रन पर ऑल आउट हो गया।

एमी जोन्स अकेली बैट्समैन थीं जिन्होंने दोनों पारियों में संघर्ष किया। हीथर नाइट और टैमी ब्यूमोंट को ऐसी विदाई की उम्मीद नहीं थी। स्नेह राणा के चार विकेट के अलावा सयाली सतघरे, क्रान्ति गौड़ और दीप्ति शर्मा ने दो-दो विकेट लेकर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई।

चोट के बाद सात्विक-चिराग की वापसी पर रहेंगी नजरें

टोक्यो,एजेंसी। भारत के बड़े बैडमिंटन खिलाड़ी, जिनमें सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी, पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन शामिल हैं, मंगलवार से टोक्यो में शुरू होने वाले जापान ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए वापसी करेंगे। एशियन गेम्स युगल बैडमिंटन चैंपियन सात्विक-चिराग पर सबकी नज़र रहेगी क्योंकि वे जून में इंडोनेशिया ओपन के शुरुआती राउंड के दौरान कंधे की चोट बढ़ने के बाद पहली बार कोर्ट पर वापसी कर रहे हैं।

ऑस्ट्रेलियन, मकाऊ, यूएस और कनाडा ओपन में हिस्सा नहीं ले पाए दुनिया की नंबर 4 पुरुष युगल जोड़ी अब ज़ोरदार शुरुआत करना चाहेगी। जकार्ता में सात्विक के चोटिल होने से ठीक पहले, ब्रदर्स ऑफ़ डिस्ट्रक्शन ने मई में सिंगापुर ओपन जीतकर बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर पर दो साल से चले आ रहे टाइटल के सूखे को खत्म किया था।

सात्विक-चिराग पुरुष युगल ड्रॉ में तीसरे सीड होंगे, जिसमें भारत के एमआर अर्जुन-हरिहरन अम्साकारुन भी शामिल हैं, जो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में लगातार क्वार्टर-फ़ाइनल में पहुँचे हैं। लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी को भी आखिरी बार इंडोनेशिया ओपन में खेलते हुए देखा गया था। दोनों टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जिमनैजियम में पुरुष एकल में भारत का प्रतिनिधत्व करने के लिए वापसी करने को तैयार हैं। इस बीच, पीवी सिंधु पिछले महीने ऑस्ट्रेलियन ओपन में अकाने यामागुची से सेमीफाइनल में हारने के बाद से एक्शन से बाहर हैं। दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट, हमवतन उन्नति हुड्डा के साथ जापान मीट के लिए महिला सिंगल्स एंट्री लिस्ट में हैं।

विश्व कप की तैयारी के लिए भारत के दिग्गज खिलाड़ी टीम में लौटे

बर्मिंघम,एजेंसी। भारत के इस सप्ताह शुरु हुए एकदिवसीय अभियान में रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के लिए राष्ट्रीय टीम में लौट रहे हैं। यह 2027 आईसीसी वनडे विश्व कप के लिए टीम की सबसे महत्वपूर्ण तैयारी की शुरुआत हो सकती है। इंग्लैंड के खिलाफ निराशाजनक टी-20 सीरीज के बाद, भारत एजबेस्टन में अनुभवी खिलाड़ियों और कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई वाली नई पीढ़ी के खिलाड़ियों के साथ नई शुरुआत करने की कोशिश करेगा।

अनुभवी तिकड़ी की वापसी से टीम में बहुत ज़रूरी स्थिरता, नेतृत्व और जीतने की मानसिकता आने की उम्मीद है, क्योंकि टीम 50-ओवर के प्रारूप में निरंतरता की तलाश में है। यह सीरीज एक नए वनडे सफर की शुरुआत है; रोहित, कोहली और बुमराह की मौजूदगी हालिया झटकों के बाद टीम का नजरिया बदल सकती है। विश्व कप में 15 महीने से भी कम समय बचा है, इसलिए हर द्विपक्षीय सीरीज और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

भारत के पास भरपूर टैलेंट है, लेकिन अब चुनौती यह है कि व्यक्तिगत प्रतिभा को एक ऐसी एकजुट टीम में कैसे बदला जाए जो लंबे समय तक सफलता बनाए रख सके। गिल, जिन्हें भारत की अगली पीढ़ी का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन्हें अपने आस-पास अनुभवी खिलाड़ियों का साथ मिलेगा। केएल राहुल के आने से मिडिल ऑर्डर भी मजबूत होगा, जिससे भारत को एक ज़्यादा संतुलित बैटिंग लाइनअप मिलेगा और वे इस प्रारूप में अपना दबदबा फिर से कायम करने की कोशिश करेंगे।

भारत का तत्काल काम टी-20 की निराशाओं को पीछे छोड़ना और वनडे क्रिकेट में नई शुरुआत करना है। टीम की सफलता न केवल खिलाड़ियों की गुणवत्ता पर निर्भर करेगी, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करेगी कि सपोर्ट स्टाफ़ कितनी प्रभावी ढंग से आत्मविश्वास को फिर से जगा सकता है और वर्ल्ड कप चरण की ओर बढ़ते हुए मोमेंटम बना सकता है।

18 साल बाद सीएसके से अलग हुए स्टीफन फ्लेमिंग

चेन्नई,एजेंसी। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ आपसी सहमति के बाद मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग का 18 साल का साथ खत्म हो गया है। यह फैसला फ्लेमिंग और सीएसके प्रबंधन के बीच कई दौर की बातचीत के बाद लिया गया। इस फैसले की घोषणा करते हुए सीएसके की मालकिन रूपा गुरुनाथ ने फ्रैंचाइजी के लिए फ्लेमिंग के योगदान की तारीफ करते हुए कहा, स्टीफन फ्लेमिंग इस फ्रैंचाइजी के लगभग पूरे सफर के दौरान हमारी कोचिंग यूनिट की जान रहे हैं। लगभग दो दशकों से, उन्होंने हमारी पहचान, विजन और बेहतरीन प्रदर्शन की कोशिश को आकार देने में मदद की है। सुपर किंग्स फ्रैंचाइजी के सभी लोगों की ओर से, हम उनकी अटूट प्रतिबद्धता, जुनून और लीडरशिप के लिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं।

भले ही मैदान पर हमारा साथ सफर खत्म हो रहा है, लेकिन वह हमेशा टीम की विरासत का एक अहम हिस्सा बने रहेंगे। फ्लेमिंग ने कहा, खेल की दुनिया में अठारह साल एक पूरी जिंदगी के बराबर होते हैं, और मैं सिर्फ आभार के साथ जा रहा हूं। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ बिताया गया समय मेरे कोचिंग करियर का सबसे यादगार अनुभव रहा है। मुझे उन सभी चीजों पर गर्व है जो हमने हासिल की हैं। हमने साथ मिलकर यादगार जीत का जश्न मनाया, मुश्किल पलों का सामना किया और ऐसी यादें बनाईं जो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। सीएसके हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगी, और मैं आने वाले सालों में भी टीम का हौसला बढ़ाता रहूंगा।

बिजनेस

भारतीय रियल एस्टेट में आया 3.2 अरब डॉलर का निजी इक्विटी निवेश

नई दिल्ली,एजेंसी। भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर में जनवरी-जून अवधि यानी 2026 की पहली छमाही में 3.2 अरब डॉलर का निजी इक्विटी निवेश आया है। इसमें सालाना आधार पर 33 प्रतिशत की बढ़त देखी गई है।

भारत में जून में खुदरा महंगाई 4.38 प्रतिशत रही

नई दिल्ली। भारत में खुदरा महंगाई दर जून में सालाना आधार पर बढ़कर 4.38 प्रतिशत (अनंतिम) हो गई है, जो कि मई में 3.93 प्रतिशत (अंतिम) थी। यह जानकारी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी डेटा में दी गई। मंत्रालय द्वारा जारी डेटा के मुताबिक, जून में ग्रामीण क्षेत्र में खुदरा महंगाई दर मई के 4.25 प्रतिशत से बढ़कर 4.74 प्रतिशत हो गई है।

बड़े उतार-चढ़ाव के बाद सपाट बंद हुआ बाजार, आईटी शेयरों ने किया कमाल

सत्र के दौरान सेंसेक्स एक समय 700 से अधिक अंक गिर गया था, लेकिन बाद में उसने सारी गिरावट को दूर करते हुए 47 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार समाप्त किया।

मुंबई,एजेंसी। वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर वैश्विक संकेतों के चलते हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार के सत्र में बड़े उतार-चढ़ाव के बाद भारतीय शेयर बाजार सपाट बंद हुआ। घरेलू बाजार के प्रमुख बेंचमार्कों ने सत्र की शुरुआत बड़े गिरावट के साथ की थी, लेकिन आईटी शेयरों में तेजी के चलते निफ्टी50 और सेंसेक्स अपने दिन के निचले स्तर से ऊपर उठकर बंद हुए। बाजार बंद होने के समय, सेंसेक्स 47.01 अंक यानी 0.06 प्रतिशत बढ़कर 77,616.40 पर था, तो वहीं निफ्टी50 0.02 प्रतिशत यानी 4.10 अंक बढ़कर 24,211 पर पहुंच गया।

सत्र के दौरान सेंसेक्स एक समय 700 से अधिक अंक गिर गया था, लेकिन बाद में उसने सारी गिरावट को दूर करते हुए 47 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार समाप्त किया। वहीं, एनएसई निफ्टी 50 मामूली बढ़त के साथ 4 अंक की बढ़त के साथ बाजार की समाप्ति की। व्यापक बाजार में, निफ्टी मिडकैप और निफ्टी स्मॉलकैप क्रमशः 0.01 प्रतिशत और 0.03 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं, सेक्टरवार देखें तो निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी मेटल में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई।

जबकि निफ्टी आईटी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई और यह 3.59 प्रतिशत की बढ़त के साथ सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला सेक्टर रहा, इसके बाद निफ्टी मीडिया में 2 प्रतिशत और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 1 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी ऑटो में 0.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.25 प्रतिशत और निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.11 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। जबकि इसके विपरीत, निफ्टी एफएमसीजी सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला सेक्टर रहा, जिसमें 0.99 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

इसके बाद निफ्टी मेटल में 0.74 प्रतिशत, निफ्टी इंफ्रा में 0.53 प्रतिशत और निफ्टी रियल्टी में 0.25 प्रतिशत की गिरावट आई। इसके साथ ही, निफ्टी फार्मा और निफ्टी एनर्जी भी लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी 50 इंडेक्स में टीसीएस में 5.51 प्रतिशत और एचसीएलटेक में 5.15 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई और ये दिन के टॉप गेनर्स रहे। इसके साथ ही टेक महिंद्रा, इंफोसिस, बजाज ऑटो और एनटीपीसी के शेयरों में 3.2 प्रतिशत से 2.2 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।

अप्रैल-जून में भारत का कुल निर्यात 11.37 प्रतिशत बढ़कर 232.73 अरब डॉलर पहुंचा

नई दिल्ली,एजेंसी। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में भारत का कुल निर्यात (वस्तु और सेवा) 11.37 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 232.73 अरब डॉलर पर पहुंच गया। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-जून वित्त वर्ष 2027 के दौरान वस्तु (मर्चेंडाइज) निर्यात 129.32 अरब डॉलर रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि (वित्त वर्ष 2026) में यह 111.57 अरब डॉलर था। वहीं, इस अवधि में वस्तु व्यापार घाटा (मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट) बढ़कर 86.86 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 68.75 अरब डॉलर था।

दूसरी ओर, अप्रैल-जून 2026-27 के दौरान सेवा (सर्विसेज) निर्यात का अनुमानित मूल्य 103.41 अरब डॉलर रहा, जबकि अप्रैल-जून 2025-26 में यह 97.41 अरब डॉलर था। इस दौरान सेवा व्यापार अधिशेष (सर्विसेज ट्रेड सरप्लस) बढ़कर 49.43 अरब डॉलर हो गया, जो एक वर्ष पहले समान अवधि में 47.90 अरब डॉलर था। जून 2026 में वस्तु निर्यात 40.41 अरब डॉलर दर्ज किया गया, जो पिछले साल जून में 34.98 अरब डॉलर था।

वहीं, जून 2026 में सेवा निर्यात का अनुमानित मूल्य 33.03 अरब डॉलर रहा, जबकि जून 2025 में यह 32.11 अरब डॉलर था। सरकार के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-जून 2026-27 के दौरान नॉन-पेट्रोलियम निर्यात 106.30 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 94.54 अरब डॉलर की तुलना में 12.44 प्रतिशत अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक, जून 2026 में वस्तु निर्यात में वृद्धि के प्रमुख क्षेत्र रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, जैविक और अकार्बनिक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक सामान तथा चावल रहे।

आंकड़ों के अनुसार, रत्न एवं आभूषण (जेम्स एंड ज्वेलरी) का निर्यात 34.64 प्रतिशत बढ़कर जून 2025 के 1.79 अरब डॉलर से बढ़कर जून 2026 में 2.41 अरब डॉलर हो गया। इसी तरह, इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्यात 20.74 प्रतिशत बढ़कर 9.51 अरब डॉलर से 11.48 अरब डॉलर पहुंच गया। वहीं, जैविक और अकार्बनिक रसायनों का निर्यात 19.42 प्रतिशत बढ़कर 2.32 अरब डॉलर से 2.77 अरब डॉलर हो गया।

भारत का स्मॉल बिजनेस क्रेडिट पोर्टफोलियो बढ़कर 49.2 लाख करोड़ रुपए हुआ

मुंबई,एजेंसी। भारत में तेजी से छोटे बिजनेस की ओर से लोन की मांग बढ़ रही है। इसके चलते स्मॉल बिजनेस क्रेडिट पोर्टफोलियो वित्त वर्ष 26 में 13.4 प्रतिशत बढ़कर 49.2 लाख करोड़ रुपए (31 मार्च, 2026 तक) हो गया है। यह जानकारी सोमवार को जारी रिपोर्ट में दी गई। क्रेडिट ब्यूरो सीआरआईएफ हाई मार्क की 'सीआरआईएफ-सिडबी स्मॉल बिजनेस स्पॉटलाइट रिपोर्ट' के चौथे संस्करण के अनुसार, इसमें सालाना आधार पर 13.4 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बढ़ोतरी के साथ, मार्च 2026 तक सक्रिय लोन की संख्या 7.5 करोड़ तक पहुंच गई है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि केवल एक व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाले छोटे व्यापार लोन में क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं। पोर्टफोलियो में इनकी हिस्सेदारी 80 प्रतिशत है और एक्टिव लोन में 87 प्रतिशत से अधिक है। कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो में 'लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी' (एलएपी) 27.1 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सबसे प्रमुख प्रोडक्ट बना हुआ है। इसके बाद बिजनेस लोन (24.8 प्रतिशत) और वर्किंग कैपिटल प्रोडक्ट (22.8 प्रतिशत) का स्थान है।

एलएपी की हिस्सेदारी मार्च 2025 में 25.5 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2026 में 27.1 प्रतिशत हो गई, जो एमएसएमई सेक्टर में सिक्योर्ड क्रेडिट के लगातार महत्व को दर्शाता है। राष्ट्रीय स्तर पर, टॉप 10 राज्यों की हिस्सेदारी पीओएस (पॉइंट ऑफ सेल) में 72 प्रतिशत है, जो कुछ क्षेत्रों में छोटे लोन के केंद्रण को उजागर करता है। आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने राज्य-वार पोर्टफोलियो ग्रोथ में क्रमशः 16.5 प्रतिशत और 18.5 प्रतिशत की सालाना ग्रोथ हिस्सेदारी के साथ बढ़त बनाई।

रिपोर्ट के मुताबिक, तमिलनाडु एक परिपक्व और मजबूत छोटे बिजनेस क्रेडिट मार्केट के रूप में उभरा है, जहां पोर्टफोलियो आउटस्टैंडिंग सालाना 11.6 प्रतिशत बढ़कर 4.6 लाख करोड़ रुपए हो गया, साथ ही एसेट क्वालिटी में भी सुधार हुआ। एंटरप्राइज टर्म लोन की ग्रोथ सालाना 4.7 प्रतिशत तक सीमित रही, जो ऋणदाताओं के लिए एमएसएमई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, सस्टेनेबिलिटी पहल और क्षमता विस्तार के लिए फाइनेंसिंग के अवसर को दिखाती है। रिपोर्ट के अनुसार, एंटरप्राइज टर्म लोन की हिस्सेदारी में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान 31.3 प्रतिशत था, जबकि सर्विस और ट्रेडिंग का संयुक्त योगदान 47.6 प्रतिशत था।

एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के आईपीओ से बाजार में बढ़ेगा भरोसा: देबाशीष मिश्रा

नई दिल्ली,एजेंसी। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की सहायक कंपनी एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी देबाशीष मिश्रा ने सोमवार को कहा कि कंपनी के 14 जुलाई को आ रहे प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) से बाजार में निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा। मिश्रा ने यहां आईपीओ के बारे में जानकारी देने के लिए आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कंपनी पूंजी की जरूरत पूरी करने के लिए आईपीओ नहीं ला रही है। कंपनी परिसंपत्ति के प्रबंधन के कारोबार में है और उसे पूंजी की आवश्यकता नहीं है। यह आईपीओ बाजार में भरोसा कायम करने के लिए है।

उन्होंने कहा, हम बाजार को गति देना चाहते हैं और इसलिए हम बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां पहले से शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं और इसलिए एसबीआई फंड मैनेजमेंट के लिए यह अगले चरण में प्रवेश की स्वाभाविक प्रक्रिया है। कंपनी का आईपीओ 14 से 16 जुलाई तक खुला रहेगा। आईपीओ के लिए शेयरों के मूल्य का दायरा 545 रुपये से 574 रुपये के बीच रखा गया है।

कंपनी ने आईपीओ से पहले 30 बडे. निवेशकों को प्राथमिकता के आधार पर 3.27 करोड़ से अधिक शेयरों का आवंटन कर 1,880 करोड़ रुपये की पूंजी जुटायी है। इनमें व्हाइट ओक कैपिटल, 3पी इंडिया, बेनेट कोलमैन, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस और अन्य निवेशक शामिल हैं। ये आवंटन 574 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से आवंटित किये गये हैं।

प्राथमिकता के आधार पर आवंटन के बाद आईपीओ में अब एक रुपये अंकित मूल्य वाले 17,09,56,631 शेयर बोली लगाने के लिए उपलब्ध होंगे। निवेशक कम से कम 26 शेयरों के लिए और उसके बाद 26 के गुणांक में बोली लगा सकेंगे। पहले किये गये आवंटन के अलावा आईपीओ से कंपनी को 9,317 करोड़ रुपये से 9,812 करोड़ रुपये के बीच पूंजी प्राप्ति की संभावना है।

कुल उपलब्ध शेयरों में 50 प्रतिशत तक पात्र संस्थागत निवेशकों को आवंटित किये जा सकेंगे। खुदरा निवेशकों के लिए कम से कम 35 प्रतिशत शेयर उपलब्ध होंगे। कंपनी के पात्र कर्मचारियों को प्रति शेयर 54 प्रतिशत की छूट मिलेगी। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के आईटी विभाग के प्रमुख श्रीनिवास जैन ने संवाददाता सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय पूंजी बाजार में अभी विकास की काफी संभावना है। उन्होंने कहा कि कंपनी देश की सबसे बड़ी परिसंपत्ति प्रबंधक है, इसके बावजूद वह अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है।

शिल्पा शिंदे के ऑर्डर पर फूट-फूटकर रोईं शिवांगी जोशी

मुंबई। टीवी की दुनिया की मशहूर अभिनेत्री शिवांगी जोशी इन दिनों रियलिटी शो 'लॉक अपः सच या सजा' में अपने व्यक्तित्व और रिश्तों को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। शो में उनके और अभिनेता हर्षद चोपड़ा की दोस्ती को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। दोनों को अक्सर एक-दूसरे का साथ देते और बातचीत करते देखा जाता है। लेकिन हाल ही में शो में कुछ ऐसा हुआ, जिससे शिवांगी रोने लगी। कंट्रोलर की भूमिका निभा रहीं शिल्पा शिंदे के एक ऑर्डर के बाद शिवांगी खुद को संभाल नहीं पाईं और फूट-फूट कर रोने लगी।

शो के नए एपिसोड में शिल्पा शिंदे ने कंट्रोलर के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए शिवांगी से कहा कि वह हर्षद के साथ अपनी बातचीत थोड़ी कम करें। शिल्पा ने कहा, "कंट्रोलर होने के नाते मैं आपसे कह रही हूं कि हर्षद से अपनी बातचीत कम कर दीजिए। मैंने सिर्फ कम करने के लिए कहा है, पूरी तरह बंद करने के लिए नहीं। मैं आपको हर्षद के साथ कहीं बैठा हुआ नहीं देखना चाहती।"

शिल्पा की बात सुनकर शिवांगी ने कहा कि यह तो बातचीत पूरी तरह रोकने जैसा हो जाएगा।इसके जवाब में शिल्पा ने अपनी बात समझाते हुए कहा कि उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि शिवांगी हर्षद से बात ही न करें। उनका मतलब सिर्फ इतना है कि वह दोनों को हर जगह साथ बैठे हुए न देखें।शिल्पा ने कहा कि उन्हें इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि शिवांगी किससे बात करती हैं, लेकिन वह बतौर कंट्रोलर अपना ऑर्डर दे रही हैं।

इस बातचीत के बाद शिवांगी काफी परेशान हो गईं। उनकी आंखों से आंसू निकल आए और वह सीधे हर्षद चोपड़ा के पास गईं। उन्होंने हर्षद को शिल्पा के दिए हुए ऑर्डर के बारे में बताया। हर्षद ने उन्हें समझाते हुए कहा कि वह परेशान न हों और रोने की जरूरत नहीं है। उन्होंने शिवांगी को शांत रहने के लिए कहा और उनका हौसला बढ़ाया।

इसके बाद शो में शिल्पा शिंदे को हर्षद और शिवांगी के आसपास चलते हुए भी देखा गया। उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि वह यह देख रही थीं कि उनके दिए हुए ऑर्डर का पालन हो रहा है या नहीं। इस दौरान शिवांगी काफी दबाव में नजर आईं। बाद में शिवांगी जोशी बाथरूम में जाकर रोती हुई दिखाई दीं।

ज़हरीली खेती पर बड़ा खुलासा

'द इंडिया स्टोरी' की टीम ने दिल्ली में उठाई जनस्वास्थ्य की गंभीर चिंता

नई दिल्ली। फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' की टीम ने दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कीटनाशक आधारित खेती के खतरनाक प्रभावों पर गंभीर चिंता जताई। इस मौके पर फिल्म की मुख्य अभिनेत्री काजल अग्रवाल, अभिनेता श्रेयस तलपड़े और निर्देशक चेट्टन डीके मौजूद रहे। सभी ने मिलकर फिल्म के जरिए समाज को जागरूक करने की अपनी कोशिश को साझा किया।

फिल्म के उद्देश्य पर बात करते हुए निर्देशक चेट्टन डीके ने कहा, "द इंडिया स्टोरी किसानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन हानिकारक रसायनों के दुरुपयोग के खिलाफ है जो चुपचाप हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। इस फिल्म के माध्यम से हम आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य को लेकर एक जरूरी चर्चा शुरू करना चाहते हैं। अगर यह कहानी कुछ परिवारों को भी अपने खानपान को लेकर जागरूक करती है, तो हम अपने मकसद को सफल मानेंगे।"

अभिनेता श्रेयस तलपड़े ने कहा कि यह विषय उन्हें व्यक्तिगत रूप से गहराई से छू गया। उन्होंने कहा, "एक अभिभावक होने के नाते यह कहानी मुझे भावनात्मक रूप से प्रभावित करती है। हम अक्सर यह नहीं समझ पाते कि रोजाना हमारी थाली में क्या पहुंच रहा है और इसका हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ सकता है। उम्मीद है कि दर्शक इस फिल्म को सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक चेतावनी के रूप में भी देखेंगे।"

वहीं काजल अग्रवाल ने भी इस मुद्दे की गंभीरता पर जोर देते हुए कहा, "मां बनने के बाद इस फिल्म को लेकर मेरा नजरिया पूरी तरह बदल गया। द इंडिया स्टोरी की तैयारी के दौरान मुझे कई ऐसे तथ्य पता चले जो बेहद परेशान करने वाले थे। यह फिल्म सिर्फ खाद्य मिलावट या कीटनाशक खेती के बारे में नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के बारे में है।"

ज़ी स्टूडियोज़ द्वारा प्रस्तुत और MIG प्रोडक्शन एंड स्टूडियोज़ के सहयोग से बनी यह फिल्म चेट्टन डीके द्वारा निर्देशित है, जबकि सागर बी. शिंदे इसके लेखक और निर्माता हैं। 'द इंडिया स्टोरी' 24 जुलाई 2026 को हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषाओं में दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

उधार की साड़ी पहनकर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में उतरी थीं कल्पना अय्यर

मुंबई। अभिनेत्री और पूर्व मॉडल कल्पना अय्यर ने अपनी जिंदगी के उस सफर को याद किया है, जिसने उन्हें एक साधारण शुरुआत से उठाकर फैशन और ग्लैमर की दुनिया में खास पहचान दिलाई। उन्होंने बताया कि कैसे एक उधार की साड़ी पहनकर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वाली एक युवा लड़की आगे चलकर फैशन जगत का जाना-पहचाना नाम बन गई। कल्पना अय्यर ने सोशल मीडिया पर अपनी पुरानी तस्वीरें साझा करते हुए अपने इस खास सफर को याद किया और बताया कि साल 1975 उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ।

कल्पना अय्यर ने इंस्टाग्राम पर अपनी पुरानी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, "नवंबर 1975 में मैंने नेवी क्वीन ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था। उस समय मेरे पास प्रतियोगिता के लिए महंगे कपड़े नहीं थे। मैंने उधार की साड़ी, अलग से लिए गए ब्लाउज और पेटीकोट के साथ इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। उस समय मेरे पास केवल मेरा आत्मविश्वास, काजल, लिपस्टिक और लंबे बाल थे, जो मेरी कमर के नीचे तक आते थे।"

कल्पना ने लिखा, "उस प्रतियोगिता में मैं विजेता नहीं बनीं, लेकिन फर्स्ट रनर-अप जरूर रहीं। इसी प्रतियोगिता के दौरान मेरी मुलाकात एक ऐसी महिला से हुई, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। साल 1975 से 1978 तक मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ, उसमें उस महिला का बहुत बड़ा योगदान रहा।"

उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, "इसके बाद मैं लगभग हर बड़े फैशन शो का हिस्सा बनने लगीं। मेरा पहला बड़ा मौका भी अचानक मिला। मशहूर मॉडल टीना मुनीम के एक फैशन शो से हटने के बाद मुझे यह मौका मिला और एक हफ्ते के अंदर मुझे दिल्ली में होने वाले शो के लिए भेजा गया। इसके लिए मुझे फैशन की दिग्गजों से ट्रेनिंग और रिहर्सल कराई गई।"

कल्पना अय्यर ने उन सभी महिलाओं का आभार जताया, जिन्होंने उन पर भरोसा किया और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। उन्होंने कहा, "इसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरा करियर लगातार आगे बढ़ता गया और मैं फैशन की दुनिया में एक जाना-पहचाना चेहरा बन गई।" उन्होंने बताया, "इसके बाद मैंने मिस टीनएज इंटरकांटिनेंटल 1976 में हिस्सा लिया, जहां मैं फाइनलिस्ट रहीं और उन्हें मोस्ट पॉपुलर कैंडिडेट का अवॉर्ड भी मिला। इसके बाद मैंने कई बड़े फैशन शोज किए और साल 1978 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया, जहां मैं टॉप 15 प्रतिभागियों में शामिल रहीं।"

विदेश

परमाणु कार्यक्रम नहीं छोड़ा तो ईरान पर प्रतिबंध जारी रहेगाः फ्रांस

पेरिस/तेहरान। फ्रांस ने स्पष्ट किया है कि जब तक ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह छोड़ने की घोषणा नहीं करता, तब तक उस पर लगे प्रतिबंधों में कोई राहत नहीं दी जाएगी।

भारत और जापान ने रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर की चर्चा

टोक्यो। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने सोमवार को जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में इलाके के हालात और रक्षा उद्योग में सहयोग पर बातचीत हुई। रक्षा मंत्री कोइजुमी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह का जापान का पहला दौरा।

अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने बढ़ाई खाड़ी देशों में हलचल, जॉर्डन ने कई ड्रोन किए नष्ट, बहरीन में बजा सायरन

कुवैत सिटी। ईरान-अमेरिका के बीच ताजा हमलों ने खाड़ी देशों की चिंता फिर से बढ़ा दी है। कुवैत ने सोमवार को कहा कि उसकी सेना एयरस्पेस में ईरानी हवाई हमलों का सामना कर रही है। वहीं, बहरीन की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, देश में सायरन बजा दिया गया है और लोगों से सबसे पास की सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है।

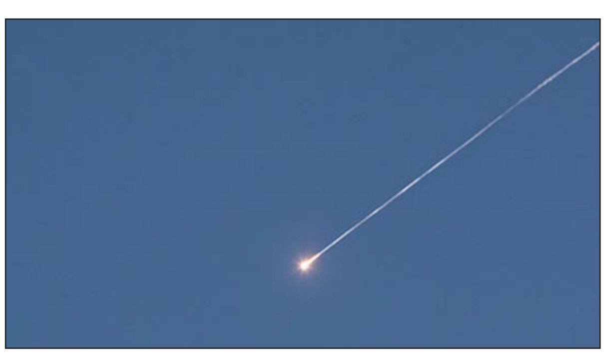

जॉर्डन ने भी कई ड्रोन को हवा में नष्ट करने का दावा किया। ईरान ने कहा कि वह उसके क्षेत्र पर अमेरिकी हमलों के जवाब में पूरे क्षेत्र में हमले शुरू कर रहा है। इस बीच अमेरिकी सहयोगियों बहरीन, कुवैत और जॉर्डन सभी ने स्थानीय समयानुसार सोमवार सुबह हवाई हमलों को लेकर जवाबी कार्रवाई की सूचना दी। जॉर्डन की सेना ने ईरान की चार मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। तीनों देशों ने रविवार को भी हवाई हमलों की सूचना दी थी।ईरान की अर्ध-सरकारी फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार, बहरीन में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने कहा कि उसकी एयर फोर्स ने ईसा एयर बेस पर हमला किया।

कुवैत की सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा बयान में लोगों से जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की और लिखा, 'सुरक्षा बल अभी कुवैती एयरस्पेस में दुश्मन के हवाई टारगेट का सामना कर रहे हैं। आर्मी के जनरल स्टाफ ने बताया है कि अगर कोई धमाके की आवाज सुनाई देती है, तो वह एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा दुश्मन के हमलों को रोकने का नतीजा है। सभी से अनुरोध है कि वे जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें।'

बहरीन के गृह मंत्रालय ने लोगों से शांत रहने और सबसे पास की सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की है। बहरीन के गृह मंत्रालय ने कहा, 'सायरन बज गया है। नागरिकों और निवासियों से शांत रहने और सबसे पास की सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की जाती है।' आईआरजीसी ने कहा कि उसने दो जहाजों को रोका, क्योंकि उन्होंने अपने ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिए थे और होर्मुज स्ट्रेट से बिना इजाजत के रूट ले लिया था।

इन दो जहाजों को रोकने के बाद हुए अमेरिकी हमलों के जवाब में मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल करके जॉर्डन में प्रिंस हसन एयर बेस को निशाना बनाया गया।जवाबी कार्रवाई के दूसरे फेज में बहरीन में ईसा एयरबेस पर अमेरिकी हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस और रिपेयर फैसिलिटी, पी-8 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट वाले हैंगर, और अमेरिकी सेना के ड्रोन ऑपरेशन के कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर पर हमला किया।'

इसके अलावा, आईआरजीसी ने बताया कि जवाबी कार्रवाई के तीसरे और चौथे चरण में कुवैत में अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाया गया।आईआरजीसी एयरोस्पेस फोर्स ने कुवैत के अली अल सलेम में अमेरिकी बेस पर फ्यूल स्टोरेज टैंक, एक पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और अहमद अल जाबेर एयर बेस पर एक एफपीएस स्ट्रेटेजिक रडार सिस्टम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया।आईआरजीसी ने कहा कि उसकी सेना ने कुवैत में अमेरिकी सेना के जमीन से जमीन पर टारगेट करने वाले मिसाइल बेस पर हमला किया। इसमें दो हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम (हिमार्स) और मिसाइलों से भरे एम्युनिशन डिपो को पूरी तरह से नष्ट कर दिया।

इस बीच, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने रविवार को ईरान के खिलाफ हमलों में पहली बार वन-वे अटैक एरियल ड्रोन और वन-वे अटैक सी ड्रोन का इस्तेमाल किया।हालांकि, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह नहीं बताया कि ड्रोन किस तरह के थे या कितनी संख्या में इस्तेमाल किए गए थे।यूएस एरियल अटैक ड्रोन का ईरान के साथ युद्ध की शुरुआत में पहली बार इस्तेमाल हुआ था।

कांगो में इबोला का प्रकोप बढ़ाः पांच प्रांतों के 1,873 संक्रमित, 672 की मौत

किंशासा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (डीआरसी) में इबोला वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। देश के पांच प्रांतों में अब तक संक्रमण के 1,873 मामले सामने आए हैं, जबकि 672 लोगों की मौत हो चुकी है। यह जानकारी देश के स्वास्थ्य अधिकारियों ने एक रिपोर्ट के हवाले से दी।

सिंहुआ ने बताया कि रविवार को जारी रिपोर्ट में शुक्रवार तक के आंकड़े शामिल हैं। इसके अनुसार इटुरी, नॉर्थ किवू, साउथ किवू, हाउत-उएले और शोपो (त्शोपो) प्रांत में इबोला का प्रकोप ज्यादा है। हाउत-उएले और शोपो को पहली बार राष्ट्रीय स्थिति रिपोर्ट में शामिल किया गया है। जांच में सामने आया है कि इन दोनों प्रांतों में मिले संक्रमण के मामले इटुरी प्रांत में मौजूद प्रकोप के केंद्र से लोगों की आवाजाही और संपर्क के जरिए जुड़े हुए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में 763 मरीज आइसोलेशन में हैं या अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। उपचार केंद्रों में बेड की कुल उपलब्ध क्षमता का 95.1 प्रतिशत हिस्सा भरा हुआ है। अब तक 306 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 299 संदिग्ध मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 91 लोगों की मौत हुई है।बुंडिबुग्यो इबोला वायरस से फैले इस प्रकोप की आधिकारिक घोषणा 15 मई को की गई थी।इससे पहले शनिवार को अफ्रीका सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (अफ्रीका सीडीसी) ने बताया कि डीआरसी में इबोला नियंत्रण अभियान में सहयोग कर रहे एक अमेरिकी मानवीय सहायता कर्मी के संक्रमित पाए जाने से स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई है।

दक्षिण चीन सागर विवादः जापान पर भड़का बीजिंग, दूत को तलब कर दर्ज कराया विरोध

बीजिंग/टोक्यो। चीन और जापान एक बार फिर आमने-सामने हैं। फिलहाल मुद्दे की जड़ में दक्षिण चीन सागर को लेकर जारी किया गया बयान है। दक्षिण चीन सागर को लेकर 2016 में आए अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण के फैसले के समर्थन में जापान सहित 14 देशों ने ये संयुक्त बयान जारी किया। इसके बाद से ही चीन और जापान के बीच तनाव और बढ़ गया है। चीन ने जापानी दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया और टोक्यो पर क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता को कमजोर करने का आरोप लगाया।

यह विवाद उस संयुक्त बयान के बाद सामने आया, जिसमें जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, फिलीपींस और कई यूरोपीय देशों ने हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के 2016 के फैसले की पुष्टि की। बयान में कहा गया कि यह फैसला अंतिम, कानूनी रूप से बाध्यकारी और चीन तथा फिलीपींस के बीच समुद्री दावों के संबंध में निर्णायक है।

चीन ने एक बार फिर इस फैसले को खारिज करते हुए इसे 'बेकार कागज का टुकड़ा' बताया। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस फैसले का इस्तेमाल बाहरी शक्तियां दक्षिण चीन सागर में हस्तक्षेप और अस्थिरता पैदा करने के बहाने के रूप में कर रही हैं।चीन की ओर से सोमवार को एक वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट किया गया। इसमें दक्षिण चीन सागर पर उसके हक और इसके जरिए विभिन्न देशों में होने वाले ट्रेड की बात है।

इजरायल में इस साल 27 अक्टूबर को होगा चुनाव, जनता करेगी नेतन्याहू की किस्मत का फैसला

तेल अवीव। इजरायल में आम चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। नेसेट के कानूनी सलाहकार सागिट अफिक ने रविवार को घोषणा की कि नेसेट 17 जुलाई को भंग हो जाएगा। इसके साथ ही इजरायल में चुनाव अपनी तय तारीख 27 अक्टूबर को होंगे। यह इजरायली कानून के तहत सबसे आखिरी तारीख है। 27 अक्टूबर को इजरायल के वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की किस्मत का फैसला होगा। इजरायली मीडिया टाइम्स ऑफ इजरायल की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, अफिक ने नेसेट हाउस कमेटी की चर्चा के दौरान कहा, "मौजूदा नेसेट अपना कार्यकाल पूरा करेगी और इसे जल्दी भंग नहीं किया जाएगा। चुनाव की तारीख कानून के अनुसार तय की गई है और यह 27 अक्टूबर ही रहेगी।"

बता दें, इससे 1988 के बाद पहली बार इजरायल में तय समय पर आम चुनाव होंगे। इसके साथ ही, यदि ऐसा होता है तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदा सरकार 1973 के बाद पहली ऐसी इजरायली सरकार बन जाएगी, जिसने अपना पांच वर्षीय कार्यकाल पूरा किया हो।यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब गठबंधन ने संसद भंग होने से पहले अपनी सबसे विवादित बिल पास कराने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

संसद भंग होने पर आम तौर पर कानून तब तक नहीं बनते जब तक गठबंधन और विपक्ष दोनों सहमत न हों। इजरायल की 37वीं मौजूदा सरकार 29 दिसंबर, 2022 को नफ्ताली बेनेट-यायर लैपिड सरकार के गिरने के बाद बनी थी।बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाली मौजूदा गठबंधन सरकार, जिसमें लिकुड, कई अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स और दक्षिणपंथी दल शामिल हैं, को व्यापक रूप से इजरायल के इतिहास की सबसे कट्टरपंथी सरकारों में से एक माना जाता है।

नेतन्याहू की सरकार के लिए हाल का समय काफी मुश्किल भरा रहा। कई बार ऐसे हालात बने, जब लगा कि इजरायली सरकार में टकराव होगा। हमास के साथ बंधक-सीजफायर डील के विरोध में, गाजा में युद्ध के दौरान कट्टर दक्षिणपंथी पार्टियों ने कई मौकों पर सरकार गिराने की धमकी दी। हालांकि, अब तक इजरायली सरकार एक साथ आगे बढ़ रही है।